There is no such procedure. I wanted to make a Special Mention on th$_e$ question of expenses involved in connection with the Commonwealth Prime Ministers' Conference. I would like to make this Special Mention tomorrow and I would like to have a commitment from you. Otherwise, it will mean, you are shielding the Government. It is clear. You do not want that this mater should be discussed, the question of the expenses involved. Rs. 200 crores are being . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This will not go on record.

SHRT SURESH KALMADI:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not allowed you the Special Mention. Therefore, I do not want to. encourage this practice that when I disallow a thing in the Chamber* the same thing is raised by some Member in the House. Then, the purpose, of disallowing i$_s$ not there, you have not given me any facts and figures in regard- to the allegation you are making in your statement. I do not know what are the facts. Therefore, I have not allowed. Please do not repat it. I have not allowed it.

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। सदन के नेता न अभी कहा है कि यहां पर विषयों का निर्णय मेरिट पर किया जाता है और सरकार एम्बेरेसिंग सिचुएशन में न आये यह बात सामने नहीं रखी जाती है। मैं आप से पूछना चाहता हूं और नेता से भी पूछना चाहता हूं कि यदि कर्नाटक डिफेक्शन वाले मामले पर हम लोग वाक्-आउट नहीं करते तो क्या आप कालिंग अटेंशन या किसी रूप में उसे मानने के लिये तैयार थे ?

श्री उपसभापति : गलत बात कहते हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : सुनिये। टेलो का प्रश्न हम लोग सामूहिक रूप से नहीं उठाते तो क्या उसकी मेरिट के आधार पर आप डिस्कशन एलाउ करने जा रहे थे ? तो साफ है कि यदि हम लोग कलेक्टिवली किसी बात को पिनपोइंट करते हैं तब आप को मेरिट मालूम होती है, यदि इंडीवीजुअली करते तो, हैं जैसा मैंने आज कहा...

श्री उपसभापति : ठीक है, बैठिये।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरिट के आधार

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Please do not record this.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. I will not allow this portion of Mr. Jha to go on record.

*Not Recorded.

CALLING ATTENTION TO A MAT. TER 01 URGENT PUBLIC IMPOR-TANCE

The law and order situation in various parts of the country with special reference to recent bomb blasts and incidents of crime i$_Q$ Delhi

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से हाल में दिल्ली में बम विस्फोटों और अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं के संदर्भ में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

E MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, the overall law and order situation in the country has not shown any marked deterioration. There has not been any

[Sbri Nihar Ranjan Laskar] major law and order situation in most parts of the country in the last few months in spite of the agitational approach adopted by some sections. Sometimes the State sponsored agitations do create problems.

The situation in Assam has shown perceptible improvement after the assumption of office by the popular Government. The Assam Government's steps to restore normalcy has been yielding results and barring a few stray incidents recently of bomb explosion, the situation continues to improve. The situation in the other North-East States and Union Territories has also shown considerable improvement.

The law and order situation in Punjab had been vitiated on account of activities of extremists and terrorists in the State. As the Hon'ble Members are aware, after the promulgation of President's rule in the State, the law enforcing authorities have been vested with additional powers to deal with the situation and various steps initiated by the State Government are eNpected to yield results.

The general law and order situation in Delhi is kept under constant review. The overall crime situation in Delhi has shown gentral improvement since 1980 though during the current year there is a marginal increase of crimes of certain categories. Recently there have been some incidents of bomb explosions which are under investigation. Many steps have been taken by Delhi Police to check the incidents of crime. These steps include increased vigilance, intensification of foot and mobile patrolling, action under preventive section of Cr. P. C. against bad characters and criminals, closer surveillance over known criminals and better liaison with police authorities of other States.

The maintenance of law and order though primarily is the responsibility of the State Governments, the Central Government also gives utmost priority to this subject. The State Government are advised and alerted suitably from time to time by the Central Government. The assistance of Central Police forces is also made available to them as and when asked for. I may assure the Hon'ble House that close vigilance on the law and order situation in the country is being maintained.

श्री सत्यपाल मलिक : श्री मान्, कानून और व्यवस्था का प्रश्न जो आज हम लोगों के सामने बहस के लिए है उस पर विचार करते समय मैं उम्मीद करता था कि माननीय गृह मंत्री जी इस विषय की व्यापकता के हिसाब से जवाब देंगे। उन का जवाब एक तरह से एक एस० एच० ओ० का जवाब है, देश के गृह मंत्री का जवाब नहीं है। इस वक्त देश में जितने किस्म की हिंसा और जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, जिस तरह का कानून और व्यवस्था की स्थिति है वह सिर्फ पुलिस के जरिये या प्रशासनिक स्तर पर अगर डील करें तो यह मसला हल होने वाला नहीं है। आज देश में हिंसा का और कानून और व्यवस्था के टूटने की कितनी ही शक्लें हैं। माननीय गृह मंत्री जी मानेंगे कि पिछले दिनों में देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। जो त्योहार, जलसे और जलूस होते थे। जो पहले शांति और भाई चारे से निपट जाते थे अब वह किसी भी शहर में शांति से नहीं निपट पाते हैं किसी भी शहर में जलूस निकलता हो चाहे वह देवी दुर्गा की प्रतिमा का हो या मोहर्रम का उसमें जो समाज के बेहतर लीग थे जो उस का नेतृत्व करते थे और शांति से उस काम को निपटा देते थे आज वे सब इरिलिवेंट हो गये हैं और गैर-जिम्मेदार लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज नेता हो गये हैं और मामूली आदमी भी कह सकता है कि जहां आजादी की लड़ाई के दौरान या उस के बाद में कभी भी दंगे नहीं देखे जाते थे आज उन कस्बों में और उन शहरों में हम दंगे देख रहे हैं और आज वहां दंगे हो रहे हैं। इसी तरह से जातीय संघर्ष हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों

को ले कर लड़ाइयां हो रही है, आसाम में जो हो रहा है यदि वैसा योरप के किसी मुल्क में होता तो उथल-पुथल हो जाती। इस के अलावा गरीब सूबे हैं। उत्तर प्रदेश है। बिहार है। वहां जातीय संघर्ष हैं। जमीन को ले कर के उस के बंटवारे का प्रश्न है। लेकिन जब उन पर चर्चा होती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब कानून और व्यवस्था के मामले पर तसल्ली के साथ बैठ जाती है और सोच लेती है कि सब ठीक है तो मैं उस से असहमत हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुल्क में बेहतर सरकार चलाना है, लोगों की रक्षा करनी है तो आज सांप्रदायिक सद्भाव का खात्मा, गरीब लोगों को अधिकारों का न मिलना, समाज में ताकतवर तत्वों के अंदर एक अजीब किस्म की स्फूर्ति और कमजोर आदमियों में एक घबराहट, जमीन का सही तरीके से बंटवारा न होना, इन सारे मुद्दों को हल करने के लिए गृह मंत्रालय को एक दृष्टि रखनी चाहिए कि आप अकेले देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को नहीं चलाते या संभालते जब तक कि आप चाहे वे फैक्ट्री मजदूरों के मसले हों या खेती मजदूरों के उन की तरफ आप ध्यान नहीं देते। यह एक आम बात और एक बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं।

अब जो राजनीतिक उग्रवाद बढ़ रहा है चाहे वह दिल्ली में बम विस्फोट हो या पंजाब में, उस से डील करने की कोई इच्छा शक्ति मुझे दिखायी नहीं देती और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि आप ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन फिर दिया तो इस से वहां की स्थिति सुधर गयी। यह बात मैं नहीं कहता, दरबारा सिंह जी ने यही बात एक इंटरव्यू में कही है कि कोई फर्क उस के बाद नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पकड़े गये हैं वे पेटी क्रिमिनल्स हैं। कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं पकड़ा गया है। जो उग्रवादी थे पंजाब के, उन के हौसले में कोई कमी नहीं आयी है। उन के जो मोडसअपरेंडी हैं वह और ज्यादा सोफिस्टिकेडेड हो गये हैं। आज से पहले वे मोटर साइकल पर कत्ल करते थे और अब, अभी एक कांग्रेस लीडर की कार में बैठ कर उन्होंने कत्ल किया है। मैं उन में से नहीं हूं कि जो यह समझते हैं कि स्वर्ण मंदिर में घुसने से ही पंजाब का मसला हल हो जायगा, हालांकि आप को एक मौका था वहां घुसने का। मैं इस बात को नहीं मानता कि राजनीतिक मसलों को सुलझाये बगैर सांप्रदायिक सदभाव को कायम किये बगैर इस उग्रवाद से आप सिर्फ पंजाब पुलिस के बल पर ही निपट सकते हैं। ऐसा मैं यकीन नहीं करता। लेकिन मैं अपनी बात को छोड़ भी दूं तो रुस्तम जी जो एक बहुत मशहूर आदमी रहे हैं, आई जी रहे हैं मध्य प्रदेश के और गृह मंत्रालय में भी रहे हैं और जिन की राय का आदर किया जाता है प्रशासनिक सर्किल में, तो उन का कहना है कि जिस समय डी आई जी अटवाल की हत्या हुई थी उस वक्त वाजिब मौका था कि जब पुलिस स्वर्ण मंदिर में घुस कर अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती थी। मैं उन की राय से सहमत हूं, लेकिन अगर आप को उन से निपटना है तो राजनीतिक और सांप्रदायिक जो मसले हैं उन को हल करने के लिये, तीनों स्तरों पर, राजनीतिक, सांप्रदायिक और प्रशासनिक, तीनों मोर्चों पर सरकार में मुझे कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखायी देती और मुझे नहीं दिखायी देता कि वे उस मामले का हल करना चाहते हैं या इस काम में वे कामयाब होन चाहते हैं।

[श्री सत्यपाल मलिक]

अब मैं दिल्ली की तरफ आना चाहता हूं। सारे देश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, दस मिनट में उस पर बहस नहीं हो सकती। गांवों में किस प्रकार लोग घरों पर बैठ कर रात गुजारते हैं, रात भर छतों पर बैठे रहते हैं इस का जिक्र करने की जरूरत नहीं। किसान के ट्रांसफार्मर और उस के बैल और उस की गाय चोरी होती है और जो सारी स्थिति है बिहार की उस को बताने की जरूरत नहीं है। वहां 16 बार फायरिंग हुई है जब से वहां नयी सरकार आयी है। बिहार में आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कि पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुए। आखिर में लाठी चार्ज हुआ, लाठी चली, गोली चली और उस के बाद पुलिस के लोगों ने दर्जन से ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया और अभी तक किसी को भी सजा नहीं दी गयी। लेकिन यह रोजमर्रा की चीजें हैं, जिनके अब हम लोग आदी हो गए हैं। मैं उन सारी घटनाओं का जिक्र इस वक्त नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो हमारे गांव हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें पुलिस प्रोटेक्शन का नहीं जुल्म का प्रतीक बन गई है। किसी पुलिस थाने में शरीफ आदमी रिपोर्ट कराने से डरता है। कम से कम आज पुलिस कमजोर तबकों के लिए, अहीर, कुर्मी, जाटव, चमार और तमाम गरीब लोगों के लए डर का कारण बन गई है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो उनको ऐक्स्ट्रीमिस्ट बताकर, डकैत बताकर बड़े पैमाने पर मारा गया। उत्तर प्रदेश में पिछले तीन साल में चार हजार से अधिक लोग गिरफतार किए गए लेकिन फूलन देवी को गिरफतार नहीं किया गया। एक सूबा तो उसकी टोह में है तो दूसरा सूबा उसकी फिल्म बनवाने के लिए तैयार है। एक सूबे की पुलिस चाहती है कि किसी बंबई के सेठ को उसकी कहानी देकर उसकी फिल्म बनाई जाए। और ये दोनों सूबे आपकी सरकार के हैं, वहां आपकी सरकारें, मगर दोनों में ताअहली की प्रतीक पुलिस बन गई। मैं दिल्ली की बात की और आकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।

श्रीमन्, जिस तरह का क्रम आज क्राइम बढ़ने का है, मैं उसका जिक्र नहीं करता। पहले तो दिल्ली में थप्पड़, चांटे की घटनायें थीं, फिर आये छोटे हथियार जो देहातों में बनते थे, कस्बों में बनते थे, देसी रिवाल्वर। अब वह भी नहीं रहे। अब बढ़िया रिवाल्वर भी नहीं है, अब जितने प्राहिबिटेड बोर हैं, 455 रिवाल्वर है, वह क्रिमिनल्स के पास हैं। स्टेनगन मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली में क्रिमिनल्स के पास हैं और हम पार्लियामेंट के मैम्बर अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो मंत्रिमंडल का फैसला होता है कि एम0 पी0 को कारबाइन का लाइसेंस नहीं दे सकते। आप नागरिकों को हथियार नहीं देंगे और क्रिमिनल्स को आप रोक नहीं सकते, उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में साफिस्टिकेटेड गैंग आपरेट कर रहे हैं चाहे रोड हांल बम हो या बैंक रोबरी हो, ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं सारी दिल्ली की बात छोड़कर प्रधान मंत्री के घर के 10 कि0 मी0 के इर्द-गिर्द जो क्राइम हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री महोदय से चाहता हूं।

1980 के पश्चात प्रधान मंत्री का घर सब से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके 10 किलोमीटर इलाकों के अन्दर के चार-छह क्राइम आपको गिनाना चाहता

हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु के घर में चोरी होती है, उनका मकान प्रधान मंत्री के घर से 6 किलोमीटर पर है। मधु दंडवते के घर में चोरी होती है, उनका मकान 6 किलोमीटर पर है। अशोक रोड पर पहले गृह राज्य मंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन साहब के यहां कोई साथी रहते हैं, उनका असलहाचोरी हो जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं। मैं इन मामलों को पर्सनली जानता हूं कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रधान मंत्री के घर से 2 सौ कदम की दूरी पर एक एम० पी० के मकान में क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, एम० पी० का सेक्रेटरी गिरफ्तार होता है, एम० पी० जमानत देता है, कोई एक्शन नहीं। प्रधान मंत्री का नाम मैं नहीं लूंगा। वह गलती हो जाएगी, लेकिन दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य का सगा साला गिरफ्तार होता है। यह बहुत दिलचस्प घटना है। दिल्ली की पुलिस कभी किसी को नहीं पकड़ती। कभी किसी की वांईचांस पिटाई में कोई बात पता चलती है तो कोई गैंग पकड़ा जाता है। उसकी थोड़ी बहुत पिटाई हुई तो वह दो दर्जन हत्याओं में, दो, तीन यहां और कुछ मेरठ में, तथा आधारें दर्जन बैंक डकैतियों में शामिल था, यहां तक कि मेरठ जिले के डिप्टी जेलर को एक क्रिमिनल के कहने से इस गैंग ने मारा। उसने बताया कि मैं इस गैंग के साथ आपरेट करता हूं। मेरी यह जानकारी है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस गैंग का एक सरगना जो मेरठ में मारा गया उसको लीडर बना कर उसकी हत्या की जांच के लिए उस संसद सदस्य ने चिट्ठी लिखी। दर्जनों कत्लों में शरीक गैंग्स्टर जब मारा गया तो उसकी जांच सी० बी० आई० को दी गयी। क्योंकि वह एक बड़ा आदमी था, उसकी हत्या की जांच सी० बी० आई० को दी गई।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब यह हालत प्रधानमंत्री के घर के चारों तरफ है, उनके इलाके की है तो बाकी दिल्ली की क्या हालत होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सारी पुलिस डिमोरलाइज्ड है। कोई आप की तरफ से इंसेन्टिव पुलिस वालों को नहीं है लोगों के क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए या उसकी जांच करने के लिये। यह बात ठीक है कि यहां दिल्ली में पुलिस दिल्ली के नागरिकों के अनुपात में सबसे ज्यादा है, इक्यूपमेंट सबसे ज्यादा सोफिस्टीकेडेड हैं। लेकिन उनकी ड्यूटी ऐसी है कि वे कभी कामयाब नहीं हो सकते। ज्यादातर पुलिस का इस्तेमाल वी आई पीं को देखभाल के लिए हो जाता है, जुलूसों के इंतजाम में हो जाता है, या मिनिस्टर साहब की सुरक्षा करने में हो जाता है। उनके पचासों फंक्शन दिन में होते हैं इसलिए उनके लिये क्राइम को रोकना मुमकिन नहीं है।

मैं गृह मंत्री जी से जानकारी यह चाहता हूं कि पुलिस कमिशन की रिपोर्ट में क्या यह नहीं है कि प्रिवेन्शन, इन्वेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन, इन तीनों के लिए अलग-अलग फोर्स हो ? जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस एक अपराधी को जेल तक लाती है। बाद में पता चलता है वह अपराधी तिहाड़ जेल से छूट गया है। वह अपराधी तिहाड़ जेल से निकल कर हिंसा, क्राइम करते हैं। जिस तरह से हिंसा होती है, क्राइम होते हैं उसके बारे में चर्चा हो जाती है और वह बाद में खत्म हो जाती है।

[श्री सत्यपाल मलिक]

कुल मिलाकर जेल से जो अपराधी बाहर निकल कर आते हैं, भाग कर आते हैं वे बहुत बड़े गेंग्स-स्टर बन जाते हैं। तिहाड़ जेल से जितने नामी अपराधी छूटते हैं हिन्दुस्तान के किसी देहात की जेल से उतने नामी अपराधी कभी नहीं छूटे हैं। इसकी वजह यह है कि जो आपका प्रोसीक्यूशन सिस्टम है वह बड़ा इनअफेक्टिव है। पुलिस के लोगों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं है, न इन्वेस्टीगेशन के लिए है, न प्रिवेंशन के लिए है और प्रोसीक्यूशन के लिए है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में आज जो स्थिति हो गई है, म उन बम विस्फोटों को तफसील में नहीं जाना चाहता, स्थिति यह है कि आम आदमी जो आपके घर से दो कदम पर रहता है वह आज अपनी सुरक्षा महसूस नहीं करता। में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बाजार के नुक्कड़ पर खड़े हो जाइये और उस पर आने वाले लोगों को देखिये, 40 से कम उम्र के जो लोग हैं उनको आप देखेंगे तो पायेंगे कि 90 फीसदी का चेहरा देखकर दहशत होगी। वे अपने आप में भयानक दिखाई देंगे। बातचीत के बीच वे हिंसा पर उतारू हो जायेंगे और हथियारों की तरफ बढ़ जायेंगे। यह एक आम प्रवृत्ति दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली एक बड़ा समुद्र है जहां सब तरह का प्रोटेक्शन रहता है। इसलिए मैं आप से कहता हूं कि दिल्ली की पूरी तरह से प्लानिंग करिये, इसको व्यवस्थित करिये। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लेफ्टोनेंट गवर्नर कहते हैं कि रात को दिल्ली को सील कर देंगे। इससे क्या होता है। क्राइम करने वाला कभी भी कर सकता है। वह थोड़े दिन ठहर जायेगा, दिन में आ जायेगा, कोई भी रास्ता निकाल सकता है। जिस दिन पालम के पास रोबरी होती है उसका पता भी नहीं चलता कि कुछ समय के बाद आई आई टी के पास फेमली को लूट लिया जाता है। उसी एक महीने के अंदर कई वारदात हो जाती है लेकिन किसी का भी पता नहीं चलता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सूरत में रात को निकलना नामुमकिन हो गया है। एक घटना जो बहुत दुखद है और शर्मनाक भी है वह मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं। मुझे दूसरे सदन के विपक्ष के एक बहुत माननीय और बुजुर्ग नेता ने बताई है। मैं उसका ब्यौरा आपको बाद में दूंगा। अगर सत्य है तो क्या यह दिल्ली को कानून और व्यवस्था पर कलंक नहीं है। उन्होंने यह बताया कि एक परिवार जिसको वह जानते हैं वह परिवार पिछले महीने दिल्ली में किसी सिनेमा हाल में सिनेमा देखने गया था। रात एक बजे सिनेमा खत्म हो जाता है। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ सिनेमा देखने गये थे। जब वह कार के पास आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी कार में पैट्रोल नहीं है तो इधर-उधर कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। सिनेमा भी बंद हो जाता है। इलाका सुनसान और उजाड़ हो जाता है। उसी समय चार लड़के उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल है। यह पेट्रोल

ले लीजिए । वह हंसी खुशी पैट्रोल ले लेते हैं । इसके बाद उन लड़कों का वह शुक्रियादा करते हैं । इसके बाद हो वे लड़कों से कहते हैं कि इस पैट्रोल का क्या दाम है । लड़के हथियार निकालते हैं और कहते हैं कि इसको वसूली दाम से नहीं होगी या तो आप लड़की को छोड़ जाइये या बीबी को छोड़ जाइये । वह अपनी बीबी को छोड़ कर चले जाते हैं । बीबी तीन-चार दिन के बाद घर पहुंचती है। इज्जत बचाने की वजह से वह पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाते । वह भी सजा देने लायक है लेकिन यह घटना सच है मैं समझता हूं कि इससे भयानक कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती है यह स्थिति दिल्ली की है हम तो यहां पर अपनी बात कहते रहते हैं और भाषण देते रहते हैं, लेकिन इससे दिल्ली की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है उस परिवार ने आज भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई । आपको इस मामले की जांच करनी चाहिए । मैं उसकी जानकारी भी बता सकता हूं ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह जो रिपोर्ट दी हैं उसमें दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति के सबंध में आपने खुद माना हैं कि इधर स्थिति में कुछ बिगाड़ आया हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में यह जो स्थिति बिगड़ी है इसका क्या कारण है ? एक्सट्रीमिस्टस का मामला अलग हैं । एक्स्ट्रीमिस्टस को पैर जमाने के लिए जगह चाहिए । असल में बाहर से जो क्रिमिनल्स दिल्ली में आते हैं और जो क्रिमिनल्स दिल्ली में है, उनके कुछ एरियाज हैं, जहां पर उनको शैल्टर मलती हैं । क्या आप इस प्रपोजल पर विचार करेंगे कि ऐसी अलग अलग एजेंसियां बनाई जाये जो दिल्ली के हर मुहल्ले का सरविलेन्स रखें और यह देखें कि यहां कौन व्यक्ति रहते हैं, उनके यहां कौन-कौन लोग आते हैं और उनकी गतिविधियां क्या हैं । अगर आप इसकी पूरी चैकिंग रखेंगे तो कुल मिलाकर जो दिल्ली की कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार लाने में मदद मिल सकती है । दूसरी बात मैं वह कहना चाहता हूं कि पुलिस कमीशन को रिपोर्ट में प्रिवेंशन , इवैस्टिगेशन और प्रोसेक्यूशन को अलग अलग करने के लिए सिफारिश की गई है, उसके संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए । इसके अलावा दिल्ली में जो बिना प्लानिंग का विकास हो रहा है, यहां पर इंडस्ट्रीज भी है और दूसरी चीजें भी हैं, इसके संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं ? दिल्ली में पेटी क्राइम्स बहुत होते रहते हैं । इसलिए लीकर के बारे में तो पुलिस को पूरी जानकारी रहती है । इन सब समस्याओं के समाधान के लिए क्या आप कोई कम्प्रेहैंसिव प्लानिंग करेंगे जिससे दिल्ली में होने वाले क्राइम्स को रोका जा सके ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think he will reply at the end if you all agree. Please note down the points.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि दिल्ली में... **(व्यवधान)** ।

DR. BHAI MAHAVIR: (Madhya Pradesh): Sir, the ruling party seems to be very greatly interested in the law and order situation in the country. The unoccupied benches are testimony to that.

SHRI RAMANAND YADAV: They are not discourteous like you. They have gone to see the Queen. The Queen of a friendly country is coming.

DR. BHAI MAHAVIR: The only discourteous person then is Shri Ramanand Yadav.

SHRI RAMANAND YADAV: They are not discourteous like you. Most of them have gone to see the Queen.

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि आसाम की सिचुएशन में सुधार हुआ है। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि इक्का-दुक्का बम ब्लास्ट की घटनाएं इधर-उधर होती रहती हैं और क्राइम्स भी होते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि क्राइम्स को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पोलिटिकल लेवल पर अगर संभव हो तो उसको ईज करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। दिल्ली के संबंध में मैं बाद में जाऊंगा। पंजाब का सवाल भी हमारे सामने है। वहां पर क्राइम्स की पोजीशन के संबंध में जरूर कार्यवाही हुई है। जब से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से कार्यवाही हुई है। लेकिन पंजाब में यह जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें जो क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स में और दिल्ली में होने वाले क्राइम्स में फर्क है। कुछ क्राइम्स पोलिटिकल होते हैं, कुछ क्राइम्स इकनोमिक होते हैं और कुछ क्राइम्स होते हैं जो शौकिया तौर पर होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं .. (**व्यवधान**) .. जी हां, बहुत से Rich people like you can take up again and commit dacoity. They develop that habit. They inculcate that habit. तो इस तरह के लोग हैं जो साइकलोजिकली इस तरह के माइंड के हो जाते हैं, धनिक होते हुए भी, संम्पन्न होते हुए भी, राजा होते हुए भी इस तरह करते हैं।

मान्यवर, आज जो पंजाब में घटनायें हो रही हैं, जो ट्रेनों का डीरेलमेंट हो रहा है, जो बसें हेल्ड-अप हो रहे हैं और जो आदमियों की हत्याओं की गई, खुले आम जो हत्यायें पुलिस के लोगों की हो रही हैं ये जो हैं यह पोलिटिकल क्राइम है और इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें सभी पोलिटिकल पार्टियों के लोगों को सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे नजर नहीं आता है कि पंजाब की पोलिटिकल सिचुएशन को ईज करने के लिये विरोधी पक्ष साथ दे रहा है। अगर वे ठीक से सहयोग दें तो उस क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ तो कहेंगे कि वहां पर मर्डर्स हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, ट्रेनों की डीरेलमेंट हो रहा है, सैबोटाज हो रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों से कहेंगे कि आप अपराध कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में इस तरह से दुधारू तलवार रखने से काम नहीं चलेगा। क्राइम्स को कंट्रोल करने में हमको, आपको, सब को सहयोग करना आवश्यक है। पंजाब के संबंध में वहां की सिचुएशन को कंट्रोल करने के संबंध में अपोजीशन का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर हमें उनका सहयोग नहीं मिलता तो पंजाब में जो क्राइम हो रहे हैं, अकेले उनको कंट्रोल करना हमारी पार्टी के लिए, सरकार के लिये असंभव है। जैसा कि आप जानते हैं वहां की स्थिति को बिगाड़ने में बाहर की ताकतें, जिनका वहां खुद अपना निहित स्वार्थ है जो देश को डिस्टेलाइज्ड करना चाहती हैं, वे वहां पर ऐसे तत्वों की मदद कर रहे हैं। आप भी सरकार के साथ सहयोग करके बैकडोर से, पिछले रास्ते से उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां की स्थिति पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो खुले आम आप लोग ऐसे तत्वों की निंदा करें। पंजाब से

हमारा पाकिस्तान का बार्डर लगा हुआ है, यह सब जानते हैं। लेकिन खुले दिल से आप नहीं कहते कि वहां पर पाकिस्तान का हाथ है। पंजाब के सम्बन्ध में आप यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आडवाणी साहब चले गये हैं, माथुर साहब हैं, कई दफा मैंने सुना और अखबारों में भी देखा कि वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का हाथ है तो प्रधान मंत्री इस संबंध में सबूत दें। लेकिन खुद जब आप भाषण देते हैं तो रात दिन कहते हैं कि साहब बाहरी हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो स्थिति है आज क्या उसमें बाहरी हाथ नहीं है, बाहरी ताकतों का हाथ नहीं है ? जो आज वहां पर अपराध कर रहे हैं, जो ट्रेनों का डिरेलमेंट कर रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, लोगों की हत्यायें कर हे हैं क्या उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं होती है। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है यह कहने की क्योंकि आप वोट के लालच में पड़े हुये हैं। इसलिये आपकी हिम्मत नहीं है ; इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि पंजाब की क्राइम की स्थिति को कन्ट्रोल करने के सम्बन्ध में आप सरकार को अपना सहयोग दें।

बिहार का जहां तक सवाल है, यह बात ठीक है कि वहां पर गोली अधिक चली है। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों का दमन करने के लिये बिहार राज्य में कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ही तत्व जो तत्व... (**व्यवधान**)... अपराध करते थे उनके ऊपर पूरी कड़ाई की जाती है। उपसभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे नये मुख्य मंत्री रात में स्वतः निकलते हैं और पटना शहर में पुलिस अधिकारियों के पास जाकर कहते हैं मेरे साथ अमुक जगह चलो। वे उन लोगों पर निर्भर नहीं करते। खुद कहते हैं कि इस मुहल्ले में चलो, वहां चलो और वहां जाकर इन्सपेक्शन करते हैं कि पुलिस अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। नये मुख्य मंत्री ने इस तरह का काम शुरू किया है, कड़ाई की है, अधिकारियों को, जो ठीक से काम नहीं करते थे सस्पेंड किया है और हिदायत दी है कि अगर ला एंड आर्डर की सिचुऐशन कन्ट्रोल नहीं करोगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। यह बात ठीक है कि वहां पर एकानामिक लड़ाई भी है और कुछ लोगों के नक्सलाइट के नाम पर मर्डर भी होते हैं और मैं यह भी मानता हूं कि वहां पर पुलिस ने जघन्य अपराध किये हैं। वे मजदूरी मांगते हैं, गरीब लोग अपना हक मांगते हैं लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जाता है इसलिये वहां पर एक तरह का इकोनोमिक क्राइम भी होता है। बड़े लोग, भूस्वामी लोग गरीबों की झोंपड़ियों को उजाड़ देते हैं। उनको भगा देते हैं। रात के समय बन्दूक ले कर के आग लगा कर उनको टेरराइज कर के भगा देते है। यह बात होती हैं। बिहार में हुई हैं लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पिपरा में जो कांड हुआ था उसमें 30–40 आदमियों को आजीवन कारावास हुआ है। बिहार सरकार ने मुस्तैदी से ऐसे तत्वों पर ऐसे भूस्वामियों पर जो गरीब तबके के लोगों पर क्राइम करते थे नियन्त्रण करने के लिये अगल-अलग विभाग बना कर और जिनकी कान्निवेंस से वे ऐसा करते थे उनको टाइट किया और पिपरा कांड में जहां हरिजन मारे गये थे वहां पर 30–40 आदमियों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई है। तो इस दिशा में सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में मेरी जानकारी इतनी नहीं है।

माननीय, दिल्ली एक ऐसी नगरी है जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं और

[श्री रामानन्द यादव]

यहां जो घटनाएं घटी हैं और जिस तरह से क्राइम हो रहा है यह दुख की बात है जो भी प्रशासन हो चाहे वह कांग्रेस का हो या जिसका हो सख्ती के साथ दिल्ली में क्राइम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि दिल्ली का पुलिस विभाग जो है वह एक्टिव नहीं है। उसमें भ्रष्टाचार फैल गया है। क्यों भ्रष्टाचार फैला है इसके भी कारण हैं। आज दिल्ली पुलिस का जो नीचे का तबका है, जो कांस्टेबल है उसके वेतन को आप देख लीजिए। हरियाणा का जो कांस्टेबल है उसकी तनख्वाह दिल्ली के कांस्टेबल से अधिक है। हरियाणा का जो थानेदार है उसको जितनी सुविधाएं मिलती हैं उससे कम दिल्ली में मिलती हैं। करप्शन तब होगा जब उसका पेट नहीं भरेगा। बड़े अधिकारी को तो हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, रहने की सुविधा है, दवादारू की सुविधा है, चलने के लिये वाहन की सुविधा है लेकिन जो नीचे के तबके का पुलिस कांस्टेबल है उसको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ चुकी है जिसकी इंतहा नहीं लेकिन आपने अभी तक दिल्ली पुलिस बल में बढ़ोतरी नहीं की है। आप जानते हैं कि दिल्ली की आबादी करोड़ों में पहुंचने वाली है। आपने उस अनुपात में पुलिस बल में कितनी बढ़ोतरी की है? आपको चाहिए कि पुलिस की बहाली को अधिक करें। दिल्ली जैसे नगर में जहां वार्डर की स्टेट में एक कांस्टेबल को अधिक वेतन मिलेगा और दिल्ली में जो कि मंहगा शहर है जहां दूसरी भी कई प्रकार की परेशानियां हैं वहां वेतन कम मिलेगा तो वह पुलिस का कर्मचारी क्या करेगा? क्या पुलिस वाला घूस नहीं लेगा? इसलिये जरूरत इस बात की है कि पुलिस बल में अधिक से अधिक बढ़ोतरी की जाए, आप दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाइये और रिक्रूटमेंट कीजिए और उनको अधिकार भी ज्यादा दीजिये। आप उनको अधिकार भी नहीं देते हैं। मुझे यह जानकारी है कि जितना अधिकार आज उत्तर प्रदेश के एक कांस्टेबल को प्राप्त है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को उतना अधिकार प्राप्त नहीं है। जितना अधिकार उत्तर प्रदेश के एक दरोगा को है उतना अधिकार दिल्ली के दरोगा को नहीं है। यह पालिसी रखने से काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली में क्राइम वे लोग करते हैं जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं और सम्पन्न घराने के लोग हैं। ये लोग सोफिस्टीकेटेड वेपंस को लेकर के क्राइम करते हैं इसलिये इन पर आपको किस तरह से नियन्त्रण करना है क्या आपने इस सम्बन्ध में विचार किया है? इनको क्राइम करने से किस तरह से वंचित करें, इस पर भी आपको सोचना चाहिए। एक बात और है पता नहीं आज क्या होता है। क्राइम में जो कारबाइन या राइफल यूज होते हैं, आर्मी का ग्रेनेड यूज होता है, देहात में बने हुये इंडीजिनियर्स पिस्टल और राइफल यूज होते हैं, मिलिटरी के गोदामों से चुराये हुये और पुलिस के गोदामों से चुराये हुये रिवाल्वर और राइफल यूज होते हैं, इन लूट-होल्ज को बन्द करने के लिये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? इस समस्या पर भी विचार किया जाए। क्या कारण है कि इतने हैंड ग्रेनेड यूज हुए। यहां जो दो सिनेमा हाल्ज में बम विस्फोट हुए आपने खुद स्वीकार किया कि पांच जगह दिल्ली में बम विस्फोट हुआ। और ऐसे लोगों ने अभी

दो दिन पहले दिन-दहाड़े घर में घुस करके एक महिला की हत्या कर दी। उसके सारे जेवर लूट कर ले गये, एक भूतपूर्व एम्बैसेडर की हत्या कर दी गई, पालम से आते हुये एक आदमी को मार दिया क्रिमिनल्स ने।

मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि आप फिगर्स बताइये कि कितने डिटेक्शन आपने किये हैं? अब क्राइम तो हो जाता है, क्रिमिनल भाग जाता है, आप उसे डिटैक्ट नहीं कर पाते हैं।

आपने कितने केसेज प्रासिक्यूशन के चलाये हैं और कितने में आपको सफलता मिली है? आपके तो प्रासिक्यूशन भी सब फेल हो जाते हैं। आप किसी को सजा नहीं दिला पाते हैं। बिल्ला, रंगा के सिवाए दो एक और केसेज में आपको सफलता मिली है, लेकिन अमूमन दिल्ली के सभी क्राइम्स अनडिटेक्टेड चले जाते हैं। आप क्रिमिनल्ज का पता नहीं लगा पाते हैं।

यहां तो दिल्ली में यह हालत है कि गोली बीस गज, तो बन्दा तीस गज। क्रिमिनल को देखते ही पुलिस का अधिकारी दुम दबा कर भाग जाता है। क्राइम होता रहता है, पुलिस का अधिकारी मोहल्ले की बगल में खड़ा है, दो मिनट में पहुंच सकता है, पर नहीं पहुंचता है। इसका कारण क्या है? कारण यह रहता है कि उसके पास उतने लोग नहीं हैं, तथा जिस तरह से क्रिमिनल्स के पास सोफिस्टीकेटेड आर्म्स हैं, उनके पास नहीं हैं। (**समय की घंटी**) उन्हें सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको वाहन दिये जायें, उन्हें अच्छी तरह से आर्म कीजिए।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामानन्द यादव : मान्यवर, सीतलवाद पुलिस कमीशन के अध्यक्ष बनाये गये, खन्ना जी भी बनाये गये। अब सत्यपाल जी ने ठीक ही कहा है—भोजपुरी में एक कहावत है, पर मैं उसे कहना नहीं चाहता हूं—एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल आफ क्राइम और इनवेस्टिगेशन और प्रासिक्यूशन तो अलग है, लेकिन उसमें भी पुलिस का सहयोग रहता है। प्रासिक्यूशन में खन्ना जी ने भी कहा था तथा सीतलवाद जी ने भी कहा था, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं।

मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस के वरिष्ठ लोग जो थे, ऐसे अनुभवी पुरुष जो थे, उन लोगों की जो रिपोर्ट आई है पुलिस कमीशन की और खास करके क्राइम के सम्बन्ध में जो है, उसको लागू करेंगे और जहां तक प्रासिक्यूशन, इनवैस्टिगेशन और कण्ट्रोल का तो अलग है, इनवेस्टिगेशन अलग कर देना, प्रासिक्यूशन को भी कम्पलीट्ली अलग कर देंगे या इस बात पर विचार करेंगे? और दिल्ली पुलिस की तथा और लोगों की बहाली करने का विचार रखते हैं, दिल्ली पुलिस दल में बढ़ोत्तरी करने का क्या आपका विचार है? क्या आप दिल्ली पुलिस को माडर्न वैपंस और वाहन और नये उपकरण देने के लिये जिससे वह क्राइम को कण्ट्रोल कर सकें और ऐसे लेजिस्लेटिव अधिकार जिससे वह सक्षम हो क्राइम को कण्ट्रोल कर सकें, देने के लिये तैयार हैं?

क्या आप इस बात के लिये भी तैयार हैं कि इस बात की इन्क्वायरी करायें कि यह नये हैंडग्रेनेड, मिलिट्री का हैंड-ग्रेनेड और मिलिट्री की राइफल और मिलिट्री से तरह-तरह के जो हथियार निकल रहे हैं, वह क्रिमिनल्स के पास कैसे चले जाते हैं?

[श्री रामानन्द यादव]

ट्रेन में डकैती होती है, ट्रेन होल्ड-अप कर ली जाती है। (**समय की घंटी**) बैंक राबरी होती है...

श्री उपसभापति : अब आप खत्म कीजिए।

श्री रामानन्द यादव : करोड़ों रुपया बैंक का लूट लिया गया है।

श्री उपसभापति : आप सारे का सारा विवरण नहीं दीजिए।

श्री रामानन्द यादव : एक पोलिटिकल राबरी है—पोलिटिकल राबरी से संबंधित बंगाल है, लेकिन और सब जगह में तो ऐसी राबरीज हो रही हैं, जो क्रिमिनल्स करते हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसा कमीशन बैठायेंगे जो इस बात की जांच करे कि मिलिट्री की आर्मरी से यह हथियार कैसे निकल जाते हैं ?

श्री उपसभापति : वह सवाल तो आपने पूछ लिया है ?

श्री रामानन्द यादव : नहीं, वह सवाल मैंने नहीं पूछा था कि यह ग्रेनेड उनके पास किस तरह से आये हैं। जैसे आपने बार्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई है या उसी तरह से बैंक्स की सिक्योरिटी के लिये बैंक सिक्योरिटी फोर्स बनायेंगे ? आज क्या होता है, राबर जाता है, 50 आदमी काम कर रहे होते हैं लेकिन डर के मारे बोलते नहीं हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्स वैसी दे देंगे तो शायद वह कण्ट्रोल हो सकेगा। क्या आप इस बात की कोशिश करेंगे ? क्या जो बेकार पढ़े-लिखे नौजवान हैं और आज क्राइम करने में लग गये हैं क्या ऐसे नौजवानों को आप बेकारी भत्ता देने के लिये तैयार हैं ? क्या आप इस बात की भी कोशिश करेंगे कि देहातों और शहरों में जो कूड बाम्ब, बन्दूक और पिस्तौल बनाने के कारखाने हैं उन को बन्द करने के लिये कड़ी निगरानी रखने के लिये राज्य सरकारों को कहें ? क्या आप राज्य सरकारों को इस बात के लिये लिखेंगे कि एनकाउन्टर के नाम पर निरीह और गरीब लोगों की जो अपनी मजदूरी मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, उनकी हत्या न की जाय ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate will continue.

सदन की कार्यवाही 2 बज कर 10 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at eleven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirteen minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shri Syed Rahmat Ali)** in the Chair.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मंत्री जी का यह कानून और व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य है उसको देखने के पश्चात निराशा हुई। निराशा इस बात की कि जो देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर कानून और व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में गुंडों और बदमाशों की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं उनको रोकने की दृष्टि से क्या उपाय किये हैं सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाये हैं ऐसा कोई ठोस कदम इसमें नहीं सुझाए हैं। श्रीमन्, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश उसके बारे में मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी पिछले सप्ताह में एक अंग्रेजी पत्रिका "आनलुकर" में उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में पूरा विवरण दिया है और उसमें दिया है कि उत्तर

प्रदेश में एक ही सरकार नहीं है बल्कि दो सामान्तर सरकारें चल रही हैं । यानी एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी द्वारा संचालित सरकार है और दूसरी सरकार विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ गुंडों के द्वारा संचालित है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो भी अधिकारी हैं चाहे वे पुलिस के अधीक्षक हों या जिले के जिलाधिकारी हों या थाने के थानेदार सभी उन लोगों के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और अगर उनके संकेत पर वे काम नहीं करते हैं तो वे वहां रह नहीं सकते । यह एक जबरदस्त प्रकार का आतंक अधिकारियों पर वहां व्याप्त है । इसका नतीजा यह हुआ है कि जगह-जगह डकैतियां, चोरियां और हत्याऐं हो रही हैं । मैं मंत्री जी से इस संबंध में कहना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश के, जैसा मैंने पहले भी कई बार विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है गुण्डे और बदमाशों के संबंध में, केन्द्रीय स्तर पर कोई इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे कि उनको दण्डित किया जा सके यद्यपि इसका जवाब यही होगा कि वह राज्य का विषय है, किन्तु समवर्ती सूची के अंतर्गत होने के कारण यह मंत्री जी का दायित्व है कि अपने स्तर पर वहां कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठायें ।

श्रीमन्, पिछली बार भी मैंने इस बात का संकेत किया था कि अब अपराध करने की प्रवृत्ति में थोड़ा सा फर्क हुआ है । गुण्डे और बदमाश तो आपरेट करते ही थे, लेकिन उनको प्रोत्साहन कुछ पुलिस कर्मी या प्रशासन के अधिकारी भी देते रहते थे । लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वे स्वयं अपराध में लिप्त हो रहे हैं । पुलिस अपराध करवाती भी है और अपराध करने में लिप्त भी हो रही है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने पिछली बार मंत्री जी को दिया था कि बस्ती जिले में सिसवा कांड और खजुवा कांड हुए । अभी मैं कानपुर गया हुआ था । कानपुर में राजपुर थाने के अन्तर्गत एक गांव में एक बड़े गरीब परिवार के घर में पुलिस के लोग घुसे । घर वालों ने प्रतिरोध किया । लेकिन वे जबरदस्ती घुस गये और उनको मारा, उनको बाहर किया, उस गरीब लड़के की बहू के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, और लोग आ गये और पुलिस भाग गई । यह पुलिस की तरफ से किया जा रहा है । इस प्रकार के जो पुलिस कर्मियों द्वारा जो अपराध हो रहे हैं, क्या इस संबंध में सरकार कुछ अध्ययन करने की कोशिश कर रही है कि ऐसी अपराधिक मनोवृत्ति क्यों पैदा हुई । मेरा कहना यह है कि पुलिस की जो भरती हो रही है उसमें अपराध प्रवृत्ति के लोगों को भरती किया गया है और साथ ही साथ चाहे जिस भी दल के लोगों से वे संबंधित हों, जो जन-प्रतिनिधि हैं, वे भी उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय हैं । क्या इस संबंध में सरकार की तरफ से जांच की गई है कि जो भी जन-प्रतिनिधि इस प्रकार की हरकत पुलिस को माध्यम बनाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी न किसी रूप में दंडित किया जाए ?

श्रीमन्, अभी कुछ साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा पूरे देश में । पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग इससे अछूता रहा करता था । पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहराइच जिला है, उसमें हमने कभी सुना ही नहीं कि वहां साम्प्रदायिक तनाव कभी हुआ । टांडा नामक नगरपालिका क्षेत्र में हिन्दू मुस्लिमों की

[श्री कलराज मिश्र]

संख्या बराबर है, लेकिन वे हमेशा सद्भाव से रहते थे । वह इलाका भी आज इस प्रकार के तनाव में ग्रस्त हुआ और वहां हरिजन घर जलाए गये प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों के भी घर जलाये गये । नतीजा यह हुआ कि निरपराध लोग उस से त्रस्त हुए । मऊनाथ भंजन में, राय साहेब उसी इलाके के रहने वाले हैं, साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ और झगड़ा हुआ । यह बहुत वर्षों के बाद हुआ है । क्यों ये अपराध किए गए हैं । कम से कम टांडा के बारे में तो मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर वहां प्रशासन ठीक होता तो गुण्डे वहां बदमाशी नहीं कर सकते थे । स्थिति सामान्य हो सकती थी, लेकिन लोगों की भावना पर कुठाराघात हुआ परगनाधिकारी द्वारा मूर्ति को अपमानित करके । जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 26-27 आदमियों के घर जलाये गये और उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने गांव में जाकर मुसलमानों के घर जला दिये । आज भी वहां तनाव बना हुआ है । बहराइच के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक ने बड़ी ही दृढ़ता का परिचय दिया । उन्होंने इस प्रकार का तनाव पैदा करने वाले एक सम्प्रदाय के वकील को तुरन्त कारागार भेज दिया गया तथा कड़ाई के साथ स्थिति को नियंत्रित किया लेकिन उन दुष्ट व्यक्तियों को भी छुड़ाने की कोशिश की जा रही है उनको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है । इन दोनों घटनाओं का जो नेचर है उसको देख कर क्या जो उपद्रवकारी हैं उनके खिलाफ मंत्री जी केन्द्रीय सरकार की हैसियत से राज्य सरकार को निर्देशित करेंगे कि इस प्रकार के लोगों को दंडित किया जाए ? ये जो घटनाएं हुई हैं इन घटनाओं के बारे में भी जांच करने की आवश्यकता है । ये घटनाए क्यों होती हैं ? इन घटनाओं को लोग जानबूझ कर करा रहे हैं । इन घटनाओं की जांच के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी करा रहे हैं । उसी मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराई जा रही है जिन्होंने गड़बड़ की है । जब ऐसे लोगों से जांच कराई जायेगी तो ऐसे लोगों को दोषारोपित करने की कोशिश की जायेगी जिनका इन से दूर का रिश्ता भी नहीं है । मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि वह अपने घर पर बैठा हुआ था उक्त घटना से उनका कोई संबंध नहीं है लेकिन उसके घर जा कर और उसको जबर्दस्ती पकड़ कर जेल में डाल दिया गया । उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है । सम्मानित व्यक्ति है । इस प्रकार की हरकतें कराई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में विशेषतौर से कराई जा रही हैं इसके कारण स्वाभाविक रूप से तनाव में वृद्धि हो रही है । अभी मंत्री जी ने बताया कि ला एंड आर्डर की सिच्युएशन बड़ी अच्छी बनती जा रही है । आज सामान्य मनःस्थिति यह बन गई है कि कोई घर से निकलता है, घर से बहू बेटी बहनें या बाकी के लोग निकलते हैं तो उनको लगता है कि घर में वापस आ भी पायेंगे या नहीं । अभी सत्यपाल जी ने उदाहरण दिया कि सिनेमा देखने एक परिवार गया, और उसकी क्या दुर्दशा हुई कहा नहीं जा सकता । यह स्थिति पूरे देश की बनी हुई है । मैं पंजाब और असम के बारे में वर्णन नहीं करना चाहता हूं । इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है । मैं दिल्ली के संबंध में जरूर यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली के बारे में यह कहा जा रहा है कि कानून और व्यवस्था अच्छी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीनों में सात बार बम विस्फोट हुआ ।

केवल बम विस्फोट ही नहीं, हत्याएं हुई हैं, अपहरण की घटनाएं तो सामान्य हैं। यह सारी हरकतें दिल्ली के अंदर होती हैं। चोरी, डकैती, बैंक राबरी आदि घटनाएं तो हर सप्ताह और हर तीसरे चौथे दिन होती रहती हैं। इस सब के बावजूद यदि यह जवाब दिया जाता है कि ला एंड आर्डर की स्थिति अच्छी है तो कितनी शर्म की बात है। मई महीने में कनाट प्लेस में वातानुकूलित सुपर बाजार में बहुत जबर्दस्त विस्फोट करने की साजिश की गई थी। बम पकड़ा गया और उसमें एक चिट पर यह लिखा गया था कि मणिपुर के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं उनकी तरफ से इस प्रकार की घटना करने की कोशिश की गई है। इन उग्रवादियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया ऐसा नहीं लगता। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं? अगर वह विशिष्ट कदम जो उन्होंने उठाये हैं उनको नम्बरवाइज बता दें तो मैं समझूंगा कि उन्होंने कुछ काम किया है। जो इनको जनरलाइज कर दिया जाता है यह उचित नहीं है दिल्ली सुलतानपुरी मोहल्ले में अभी सितम्बर मास में फायरिंग हुई। इस संबंध में पुलिस ने कहा हमारे पास अश्रुगैस के सैल नहीं थे इसलिये हमने गोली चला दी। यह इनका जवाब है, अश्रुगैस नहीं इसलिए गोली चला दी। लोगों की जान चली गई। क्या इतनी सस्ती है लोगों की जान। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाई की। इसकी जांच कराई या नहीं। इस बात को भी सामने उभर कर आना चहिये तभी हम समझेंगे आप ने कुछ किया।

जहां तक पुलिस कर्मियों के अपराध का ताल्लुक है अबतक अपने जीवन के बारे में अपनी स्वयं की सुरक्षा का अनुभव नहीं करेंगे कि हम भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित हैं तब तक उनके अंदर भ्रष्टाचार और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। हमारे रामानन्द जी ने इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों के वेतन को बढ़ाने की दिशा में भी सरकार की तरफ से प्रयत्न होने चाहियें। उन सब लोगों को अपने परिवार की तरफ से निश्चिंतता रहनी चाहिये। इस दृष्टि से सरकार को ध्यान देना होगा। उनको आर्थिक दृष्टि से व्यवस्थित करने के लिये वेतन बढ़ाने की बात करनी चाहिये ताकि वे व्यवस्थित हो कर काम कर सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां आप उनके वेतन में बढ़ोत्तरी करें वहीं उनको समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए ताकि पुलिस मैन समाज में लोगों के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार कर सकें। मैंने सुल्तानपुरी की फायरिंग के संबंध में आपसे पूछा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने सुल्तानपुरी की फायरिंग के संबंध में कोई जांच बैठाई है या नहीं बैठाई है? अगर आपने कोई जांच की है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर आपने क्या कदम उठाये हैं? ये मेरे कुछ सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में उन पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया है उससे

[श्री शिव चन्द्र झा]

यह साफ है कि बात कम्प्लीमेन्सी है, यह सरकार आत्म-संतोष से ओत-प्रोत है । वह कहती है कि सारे देश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है, दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है । उनका कहना है कि कोई चिन्ता की बात नहीं है । थोड़ा-बहुत इधर-उधर स्थिति में खराबी है, वह ठीक हो जाएगी । मैं समझता हूं कि यही दृष्टिकोण है जो बहुत खतरनाक है । थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि देश में अमन-अमन की स्थिति ठीक है, दिल्ली में सब कुछ ठीक है तो फिर ये अपराध क्यों हो रहे हैं ? आपका कहना है कि आसाम और पंजाब में जो थोड़ी बहुत हालत खराब है उसको भी टेकल कर लिया जाएगा । सवाल यह खड़ा होता है कि किसी एक बिन्दु को लेकर सन् 1980 से लेकर अब तक लॉ एण्ड आर्डर की जो स्थिति देश में चल रही है क्या उसके संबंध में जांच करने के लिए कोई हाई लेवल कमेटी या कमीशन कायम किया है ताकि देश को यह बताया जा सके कि ये अपराध किन कारणों से बढ़ रहे हैं । आज देश में लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है दिल्ली में हिंसा की और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं । ये किन कारणों से बढ़ रही हैं, क्या आपने इसकी जांच की है ? श्री चव्हाण साहब जब होम मिनिस्टर थे तो उस वक्त होम मिनिस्ट्री ने एक कमीशन की बहाली की थी और उसकी रिपोर्ट भी सामने आई थी । ऐसी स्थिति में क्या आप हमारे देश में जो अमनोअमन की हालत में खराबी आती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जांच करने के लिए कोई हाई लेवल कमेटी या कमीशन मुकर्रर करेंगे । सन् 1980 से अब तक हमारे देश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति किस प्रकार की रही है, ताकि इसकी जांच हो सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अपराधों की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते हैं, सरकार उन पर अमल नहीं करती है । साम्प्रदायिक दंगों को लेकर जो हिंसा होती है या जो दंगे फसाद होते हैं, उनके बारे में कई बार इस सदन में कहा गया कि पंचायत लेवल पर पीस कमेटीज बनाई जानी चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है । ब्लाक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, अगर पीस कमेटीज या शांति कमेटियां बनाई जाएंगी तो वे व्यवस्था में सुधार करने में बहुत मदद कर सकती हैं । इन कमेटियों को बनाना मुश्किल काम नहीं है । पुलिस की मशीनरी होने के बावजूद समाज में ऐसे निष्पक्ष लोग भी हैं जो लोगों में सद्भाव पैदा करना चाहते हैं । इसलिए क्या आप इस प्रकार की पंचायत लेवल पर और ब्लाक लेवल पर परमानेन्ट कमेटियां बनाएंगे जो शांति स्थापित करने में मदद कर सकें । मुरादाबाद में या बिहार शरीफ में या जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनमें ये कमेटियां कारगर काम कर सकती हैं । तो इन अपराधिक घटनाओं में बैंक रोबरी, मैं चंडीगढ़ की बात नहीं करता हूं वह पंजाब का अलग मामल है, दिल्ली में भी बैंक रोबरी की घटनाएं इ घटी हैं और घटने की संभावना है । सके लिये खुद तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह जी ने यहां पर कहा था कि हम बैंक सिक्योरिटी फोर्स के बारे में विचार करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस है, इंडस्ट्रीज के लिये अलग सिक्योरिटी फोर्स है । उन्होंने कहां था कि जहां-जहां पब्लिक सेक्टर हैं उनको बचाने के लिये इस तरह की

फोर्स पर विचार करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सफाई के लिये मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन है । यहां से होम सेक्रेटरी वहां बैंक कर्मचारियों को कहता है कि बैंकों में डकैतियां हो रही हैं, इसलिये आपको बैंकों की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, कैश कम रखें उसका प्रोटेक्शन करें । क्या नायब तरीका है ? जो कर्मचारी नोट गिनता है उसको कहते हैं कि रक्षा तुम करो । वह कैसे रक्षा करेगा । उसके पास न लाठी है न छड़ी है वह कैसे रक्षा करेंगे, बिल्डिंग की कैसे रक्षा करेगा । इसका मतलब यह है कि आपने बैंक सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सोचा नहीं है । ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनका संबंध सारे देश से है और इस बारे में मैं देख रहा हूं कि आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं । इन सब बातों को लेकर पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट है, उप-सभाध्यक्ष महोदय, जरा पूछिये कि क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर अमल किया है । उसमें बहुत से कन्स्ट्रक्टिव सुझाव भी हैं जैसा कि पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वह कैसे हो ताकि अपराधियों से तुरन्त निपटा जा सके, कैसे अश्रु गैस छोड़ी जाय, कैसे रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाय । इन्होंने उसे इम्प्लीमेन्ट नहीं किया । सरकार की तरफ से ही कमीशन की बहाली होती है और जब उस कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसको भी यह सरकार इम्प्लीमेन्ट नहीं करती है । नतीजा यह है कि परिस्थितियां आज दिन-ब-दिन बिगड़ती ही जा रही हैं ।

जहां तक दिल्ली का सवाल है, मैं असम और पंजाब का जिक्र अब नहीं करना चाहता हूं । पंजाब और असम के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है और वह रिपोटीशन हो जायेगा । यह हकीकत है कि आज अमन और अमान की स्थिति बिगड़ती जा रही है । यह क्यों बिगड़ती जा रही है मैं निजी तौर पर कहूंगा कि इसकी वजह समाज की आर्थिक हालत जो दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है वह है । देश में बेकारी बढ़ती जा रही है, इसका रूट काज यह है। अमेरिका में भी डकैतियां होती हैं, इग्लैंड की रानी जो यहां आ रही है, चोर उनके बेड पर चला गया था । आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनके बेड पर चोर बैठ गया । कैसे वह चोर बकिंगम पैलेस में पहुंच गया वह एक रहस्य, है, मिस्ट्री है और सोचने की बात है ।

उपसभापति (श्री सैयद रहमत अली) हमारे होम मिनिस्टर क्या इसका जवाब भी देंगे बकिंघम पैलेस में चोर कैसे घुस गया

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह घटनायें खुशहाल मुल्कों में भी होती हैं । अमेरिका में भी देखें तो वहां की इकानामिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वहां की भी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है । मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति की वजह से हर जगह बात बिगड़ रही है । गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है । आप कहेंगे कि यह चीज हमारे दायरे से बाहर है । मैं मानता हूं लेकिन इसकी जड़ में यह है ।

जहां तक दिल्ली का सवाल है मैं कहूंगा कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चार हमारे नगर ऐसे हैं जहां पर

[श्री शिव चन्द्र झा]

आपको विशेष ध्यान देना होगा । इनकी समस्यायें गम्भीर हैं, ये बहुत कन्जेस्टेड नगर हैं और वहां पर इस तरह की घटनायें होने की संभावना ज्यादा होती हैं । तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं । इसीलिए एक स्पेशल प्लान क्राइम रोकने के लिए दिल्ली, बंबई, मद्रास और कलकत्ता के लिए बनाने पर आप विचार करें । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । और शहरों में क्राइम रोकने के लिए आप बंबई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता को एक आदर्श बना देंगे । तो इससे बहुत बड़ी रोशनी फैलेगी । चारों तरफ इसका बहुत बड़ा असर होगा । क्या आप इस पर विचार करेंगे ? आप दिल्ली के लिए और इन तीन बड़े नगरों के लिए क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल प्लान बनाइये । जहां तक दिल्ली का सवाल है आप खुद बतावें कि जब से आप पावर में आये हैं हर साल 1980 के मुकाबले में 1981 में क्राइम बढ़े हैं, 1981 के मुकाबले में 1982 में क्राइम बढ़े हैं, 1982 के मुकाबले 1983 में कर्व ऊपर जा रहा है । आप बताएं कि क्या यह कर्व ऊपर नहीं जा रहा है ? जनता सरकार के समय के कंटेस्ट में भी आप जवाब दे सकते हैं । लेकिन जनता में बहुत कुछ अच्छा रहा, शासन में बहुत कुछ अच्छा था । खराबियां हमीं में थीं । यह बात अलग है लेकिन शासन के तरीके में बहुत सी बातें अच्छी थीं । आप यह बतावें कि क्या कर्व 1980 से ऊंचा जा रहा है या नहीं ? मैं कह रहा हूं कि ऊंचा जा रहा है । अन्त में उप-सभाध्यक्ष महोदय, पुलिस स्ट्रक्चर की बात करते हैं । बहुत सी बातें दी गई हैं यह बात बिहार में भी होती है और दिल्ली में भी है कि पुलिस का भी खुद का हाथ रहता है क्राइम को बढ़ाने के लिए क्योंकि इससे वेपलते हैं, बढ़ते हैं और एग्जिस्ट करते हैं । मेरा कहना यह है कि उसके मानस को बदलने के लिए पुलिस के स्ट्रेक्चर को बदलने के लिए आवश्यकता है । पुलिस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उनको लागू किया जाए । इनके स्ट्रेक्चर में बुनियादी परिवर्तन का तरीका यह है कि इस विंग को आप इलेक्टिव बनावें । पुलिस का हैड कमिश्नर जैसे दिल्ली का है जनता द्वारा चुना जाए । आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे होगा । आप चुन कर के आते हैं, मैं भी चुन कर के आता हूं; एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस में जो हैड है उसका भी चुनाव हो तो यह कोई असंभव बात नहीं है । दुनिया में अभी भी यह होता है । कई पूंजीवादी राष्ट्रों में इस प्रकार की प्रथा है इसलिए आप इस सेवा को सोशल सर्विस ओरियेंटेड बनाएं । आफिशियलडम या डोमीनेशन माईंडेड अभी पुलिस का स्ट्रेक्चर है और यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है । इसको बदलना होगा । दूसरे मुल्कों में वातावरण दूसरा है । जैसे सिविलियन हैं पुलिस वालों को सिविलियन इन यूनीफार्म समझा जाता है, सिविलियन विद एन आर्म और जब हमारी पुलिस का सवाल आता है तो फर्क पड़ जाता है । हमारी पुलिस में एक डोमीनेशन की, बहिष्कार की, टेरर की बू आती है । इसलिए उनको सोशल सर्विस ओरियेंटेड बनावें । इसीलिए मेरा कहना यह है कि यह इलैक्टिव हो । ये सब कदम आप उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि अमन-अमान की स्थिति होगी । इसमें आपको विरोधियों को पूरा कोआप्रेशन होगा बशर्ते कि आपकी भावना साफ हो और आपकी नीयत साफ हो । इसलिए मैंने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब आप दें ।

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, the statement read out by the hon. Home Minister shows that the Home Ministry is very complacent and is not aware of the seriousness

of the situation. The Prime Minister, during the course of just one month, thrice warned the nation that some foreign forces are attempting to destabilise not only in Punjab, but elsewhere also. Does the Home Ministry realise the connection between the breakdown of law and order and the forces which want to take advantage of the present situation? Sir, I would like to bring to the notice of the Government—it is not that they are not aware of it; but they would not admit it—as to what we think, my Party thinks, are the reasons for this so-called breakdown of law and order. The primary reason is religious and communal forces. They are inciting clashes and they are making determined efforts *in* that direction. The second aspect of this break-down of law and order is politic'al murders and killings and the third aspect is separatist forces resorting to terrorist activities. Then comes the last aspect, that is, crimes by pure criminals in the form of dacoity, robbery etc. In all these things people are the victims. Again, the role of the police, the police thrmselves behave like criminals in some cases. So, how does the statement show the Government is aware of all such things and that they are inclined or they are going to take determined steps to mobilise all the forces interested in peace-full life, interested in democracy, interested in national unity, to come together and face the situation? There is no indication like that.

Now let me first touch the religious and communal aspect. Even in a State like Patna which has a glorious tradition of culture and civilization, in the name of religion Anand Margis want to take out a procession with human skulls and daggers in their hands. What is the implication of such an activity? What steps the Government is taking in this connection, I want to know. Then, in many towns in U.P., earlier my friend was talking about the communal clashes in Tanda and other places. What are the reasons for such communal clashes? *(Interruptions)* T am coming to that. Recently my party published a pamphlet. Its title is 'Vishva Hindu Parishad, the RSS broad outlook'. All of us are aware of this *'ekatinata'* or whatever you may call it. I am unable to pronounce it properly. Such is the gap between Tamil and 'ekatmata', that is oneness of Hindu religion. They have started the yatra. They are going up to Kanyakumari and Rameshwaram. At least South was free from such trouble in the past. Is it not an attempt to take this cult in the name of Hindu religion and spread it throughout the country? We really want the Ganges and the Kaveri to be united. Kashmir and Kanyakumari, Rameshwa-am and Varanasi were the symbols of Indian unity. But what is the purpose of this yagna? They think the danger does not come from outside, from American imperialism or through Zia-ul-Haq's regime. They think danger does not come through Indian Ocean. For these people the danger comes only from the minority in this country. Is it not diversionist? Is it not an attempt to shield the real culprits from whom me danger comes to our country? So, their is the performance in the name of Vishwa Hindu Parishad. This pamphlet it sold in our book shops. But rowdy elements enter our book shops and threaten: "If you sell these books, we will set fire to your book shops". I am myself feeling whether I will be safe in Delhi if T speak the whole truth and attack the RSS or the Vishwa Hindu Parishda and expose those political parties which are behind those communal forces. What will happen, I do not know. I cannot forget what happened to Kamraj in this very city in the name of religion. Earlier I cannot forget what happened to Mahatma Gandhi in the name of religion. These are the real forces which are threatening and creating law and order problems. Tt is not just law and order problem which can be controlled by police and arms. It is a very serious threat, with deep-laid plans. This is elementary, the first stage—this Yagna, or padyatra, or rath yatra because how can they afford to walk such distances; so it is rath yatra. This is the first preparation. Worse things are yet to come, after they complete the yatra. And what is ti» attitude of our ruling Congress in this

[Shri M. Kalyanasundaram]

respect? The lulling party is pledged to secularism and democracy and even socialism. That is what our Constitution says. But they jSwant to softpedaJ; thefr want to woo the Hindu masses also. They want to show that they are more Hindu than the Vishwa Hindu Parishad. Such an attitude will never help us to free people from these obscurantist and super-litious ideas in the name of religion. All ious faiths should coexist. Whether il is Hinduism or Islam or Christianity 01 Buddhism, they should co-exist. They are meant to serve the people and not to kill the people. Killings are taking place in the name of religion, in the name of God. So when we expose them, we are exposed to danger, but we Communists are prepared to face the danger in the interest of national unity.

Let me come to the political murders and killings. I do not want to narrate all the ietails of communal clashes which have taken place in the recent period lest it Id add to the communal feelings. Now *take* political murders. Who is behind these political murders? Political murders take place most in Gongress(I) led States. Let me take, for instance, Bihar, In Bihar, 43 Communist activists and leaders have been killed during the past two years. Even on 13th of this month, Shri Baban Singh, one of our important active leaders in the 1 iiral areas, was killed. He was preparing for the march organised by the Communist Party of India in Patna or the i 5th. While he was returning with his

[leagues, he was waylaid and killed in day time. Like that 43 Communists have lost their lives in the recent period under ,gress(I) rule. Who ar$_e$ those people? They take shelter under Congress(I). Some of them are in the Youth Congress. Is this the way of building the Congress? We Communists will • not quarrel if you

Id yourself up on the basis of past tradition and service to the people and not by killing and terrorist methods. It won't help you to build your party.

Nor will you succeed in suppressing us — rest assured. During the time of the Britishers you struggled for thirty years and you are still existing. So, don't use this police against the communists, workers and farmers. When workers and farmers agitate, the police is very brave. But I would tell the police, lot them show their bravery to those terrorists. They are shivering. This morning while answering questions, the Home Minister was talking about the Golden Temple. Nobody who is interested in the solution of the Punjab problem would suggest that police or army should be sent into the Golden Temple. That is absurd; that is a wrong advice; we are not for that. But can he say that all these wanted people whom he had mentioned are taking sheltor all the time inside the Golden Temple and eating all the time inside the Golden Temple? Are they not coming out and roaming about? Has the police the courage to touch them? They wjll just salute them and go away. They can only kill ordinary workers, farmers and communists when they struggle against exploitation and poverty as was done when we communists struggled in the district of Begusarai in the State of Bihar among tribals and poor people. This is how you are helping the poor and weaker sections of the society-by beheading their leaders. These are matters which you should consider more seriously.

Then, Sir, in Orissa we ourselves condoled the death of Mr. Lakshmana Maha-patra—he was an honourable Member of this House—who was murdered in daylight. Can the Home Minister gives us details of afl these political murders? Even if some opposition parties had killed some Cong-ress(I) workers, come, tell us. We will understand. I do not want to attack only the ruling party which is responsible for killing workers of opposition parties. If any opposition party has done the same thing against the ruling party, come and tell us and let us understand why and how it happened. Politics of murder should be eschewed if democracy is to be saved. When we communists have agreed to work in *a* parliamentary democracy, it is the responsibility of the ruling party to observe democratic norms and give full freedom for mass struggle, and the camps that we communists are conducting in this country in favour of the workers and peasants.

Then, Sir, a few words about feuds and crimes by professional criminals and da-coities and robberies. Of course, in Delhi and other areas, robbery of banks was taking place. We are not sure whether some robbers themselves have been committing robberies and putting the blame on terrorists or whether the terrorists themselves have been doing it for collecting funds. These are matters to be seriously considered. We thought these robberies, house-breakings, thefts and killings take place only around Delhi and in this area. Now this cut is invading the south also. Recently, before I left for Delhi, there were two instances of robbery and theft there. It is said that the robbers, came from the north. I do not know whether the Tamil Nadu police wants to escape from their responsibility by putting the blame on robbers from the north and thus hide their inability to apprehend the culprits. So, the cult of robbery and dacoity is spreading all over the country. The cult of violence is spreading. Does it have any soci'al purpose, does it hav$_e$ any political aim? Yes, they have a political aim. Is there any social purpose or economic objective? They want to create chaos in this country so that our development may suffer, our democracy may be threatened. So this is a very serious situation that is developing. I am very soTry that the Home Minister is not here. He must have been here. This is a very important question, more important than the one he may be attending to at this time. He must take the responsibility to answer all these questions. I have posed the questions. Let him assure me that he will investigate into all the political murders, the murders in Bihar, Orissa and other parts of the country, whether it is a Congress(I) State or a non-Congress (I) State. Then the crimes by the police. The police themselves are responsible for committing rape and killing. They commit rape against women. They take women to police station and rape. There are several instance in this sphere. How are you going to check the police? They kill extremists and put up this theory of encounter. Political extremists, those who are of Naxalfte persuasion, are killed; and it is shielded in the name of encounter as if they tried to kill the police people- This Is also be-**1146 RS—9** coming horrible. What steps is the Government going to take to assure the people about safety to their life and property? This is the question I want to pose. Another thing is, to save not only the minority comunity but even the majority community from- these communal clashes; what steps is the Government going to take? What happened to the National Integration Council? Will they take the Oppositiion parties into confidence? Will they try to make efforts to bring the secular forces and the democratic forces together to face this menace? You or your administration—when I say *you'.* I mean the Government, the ruling party, and the administration—is so corrupt and demoralized that you carrnot face the serious threat that is facing our country. We must unite the people from below. Allow them to organize; allow them to conduct their struggles for economic relief, in the case-of people like farmers and the working class. It is the capitalists and imperialists who are financing these forces to divide the workers, to divide the farmers, so that they can destabilize the country more successfully.

These are very serious matters, and the Government must take serious steps.

Thank you.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I am constrained to say that the hon. Home Minister's statement betrays a completely complacent attitude to the problem we are discussing. The earlier speakers had cited many examples to show how the incidents of criminal activities are increasing and, at the same time, the law and order situation in general is deteriorating. I will only quote one particular figure given by the Minister of State, Mr. Venkata-subbaiah, yesterday in the Lok Sabha to show how complacent they are in today's statement. Yesterday, in reply to a Starred Question in the Lok Sabha, the Minister of State. Mr. Venkatasubbaiah stated that during the months from January to October 1983, in Delhi alone in total 23,067 cases of crime—or the crime figures: as they have skid—have been registered whh the police: and out of these **210** Incidents

[Shri Dipen Ghosh]

of murder had taken place in Delhi itself during the last ten months.

3 P.M.

And if 1 calculate, the monthly average comes to 21 murders. It means that every month on an average 21 murders have taken place during the period of the last ten months. And in totality, if we come to daily average of 23,067 cases, it comes to 76.26. The cognizable criminal activities recorded with the police in Delhi come to 76.26 daily. Naturally, this figure itself will show how the incidents of crimes are increasing in Delhi, the capital of our country, the centre of the entire state power.

Sir, in the statement of the Minister made here, I see that the situation in' Assam and also in Punjab is sought to be painted as the problem of law and order because these paragraphs have been included in this particular statement while discussing the law and order situation.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Assam and Punjab are in a separate category.

SHRI DIPEN GHOSH: And of course in this House we have discussed these two matters, and even in this session we discussed about Punjab. But can the Central Government and for that matter the ruling party at the Centre absolve its responsibility for the deterioration of the law and order situation or whatever you call it in Assam and Punjab? And what steps have you taken? In fact all these extremist activities or whatever you are calling in Punjab or somewhere else are all state inspired. You have used the word in the first paragraph. You have said;

> "Sometimes the State sponsored agitations do create problems."

I do not know what the hon. Ministry seems to mean by it But State means the state power. In that case, from the English word the derivation comes that the Central Government sponsored agitations do create a law and order problem. This sentence fn English gives that meaning of the State sponsored agitations.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA (Assam): It is correct because the Government has been doing it.

SHRI DIPEN GHOSH; The Central Government.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: They mean the State Government of Tamil Nadu and West Bengal.

SHRI DIPEN GHOSH: But the words "State sponsored" mean "sponsored by state power". As no State Government has any state power, the Central Government only can be considered as "State'" from the point of view of the meaning.

SHRI M. KALYANASUNDARAM. Some Under Secretary must have dratted it and the Minister has read it out

SHRI DIPEN GHOSH: In your statement you have said, and I quote:

> "The Assam Government's steps to restore normalcy has been yielding results..."

And it continues;

> ". . .and barring a few stray incidents recently of bomb explosion, the situation continues to improve."

What he says is:

> "... barring a few stray incidents..."

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: ft is a fact.

SHRI DIPEN GHOSH; Then, wou d you kindly consult the statement, the speech, made by your Government's Prime Minister On the 12th in Assam? What did she say? Did she say that these were stray incidents, stray incidents of bomb explosions? You kindly consult the speech rendered by the Prime Minister of our country when she visited Assam recently.

This is the altitude of the Ministry of Home Affairs to this particular point, towards the situation in Assam. On the situation arising out of the explosions, bomb explosions and other activities in

Assam, the Minister of State for Home Affairs is saying that these are stray incidents whereas the Prime Minister made broadsides, taking a clue from these incidents. So naturally I think that the Minister of State for Home Affairs, who has made the statement here, should again go through the statement and modify it because this completely betrays a complacent attitude of the Government towards this particular problem. This is a vary serious problem.

My colleague, Mr. Kalyanasundaram has sor.p[ht to classify the causes of crimes Or rath i r the causes which led to such crims. Naturally that is totally absent in the statement. In our country today, though the Government is very adept at citing *O]*-painting any kind of murder or anything else as a problem of law and order, in », class-divided society like ours, murder takes place at the instance of the landlord murder takes place at the instance of the industrialists. . .

SHRI M. KALYANASUNDARAM: By the goondas of the capitalists.

SHRI DIPEN GHOSH:.... by the goondas of the capitalists and those goondas are protected by the State, the Central Government and the State power. So naturally if we go through the causes of these crimes in our country today, what *do* we find? Harijans are being killed. Who am killing the Harijans? Workers are beirg killed. Who are killing the workers? Common people are being killed. Who are killing those common people? Who are the people who are behind those killers and who are the people who are protectinc those killers? Will the Minister of Home Affairs kindly state how many people involved in these 210 murders in Delhi have been apprehended? Will the Minister kindly state in how many esses, his Government has gone into ideiitifyine the causes for such murders or for such criminal activities? So naturally if we look to the problem simply from the point of view of law and order, I would like to sav that we would minimise the problem *or* we would not give adequate importance to the problem because behind whatever is taking place in our country in the name of murder, in the name of killing, in the name of rape, in the name of dacoity, in the name of burglary, deep-rooted causes are there. social causes are there, economic causes are there. And mors so, these people who are at the helm of affairs are mostly responsible for these types of crimes. So I would like to know from the Minister of Home Affairs whether his Government is prepared to make a survey of the causes of the increasing incidence of criminal activities and whether the Government is prepared to nip those causes in the bud. So it is not a question of simply increasing the number of policemen nor even a question of increasing the salary of the policeman. Yes, the policeman's salary has to be increased. If the salary of a Member of Parliament can be increased, the salary of the policeman should be increased. The Home Guard's salary should be increased—those who are put on this type of job. Uufor-tunately the people who are running *(he* Government, who are so inclined to raise the salary of a Member of Parliament are not inclined to raise the salary of the P°°r policeman or the Home Guard, who are asked to do the job of containing the criminal activities.. So I will surely urge the Government to consider that point too, as my other colleagues have stated. *(Time-belt rings)* One minute. I want only to say that as the incidents of crime are increasing in our country the socioeconomic situation, rather the socio-politi-co-economic situation, of our country ia mainly responsible, and the ruling party at the Centre, and for that matter, the ruling classes, are sponsoring all these things. So> naturally the Government should take note of these things and should make a survey about the causes and should take steps to create a situation whereby the causes of these criminal activities or these crimes can be eliminated.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): I am in full agreement with the speaker who preceded me that the statement of the honorable Home Minister is a very, very disappointing statement. It appears from the statement that the Government has not been able to take into account the serious situation in this country. He says that

[Shri Dinesh GoswamiJ

there has been no marked deterioration. I do not know where he draws the distinction between deterioration and marked deterioration. There is an air of absolute violence in this country which the Government fall$_s$ to note. No citizen, however honest he may be, is safe, whether in Delhi or in other parts of the country. Nobody when he goes in a train can reasonably feel sure and secure that he will reach the destination ot reach the destination unharmed. Nobody when he travels even in Delhi in a car or bus or taxi is sure that he will not be robbed. There is a total air of violence which unfortunately the honourable Minister fails to take note in his statement. And the violence has many facets. For example, some of my friends say that this is because of economic reasons. But if ypu look to the violence in Delhi, all the car robberies that have taken place, have been done by boys from affluent houses; they have not been done for economic reasons. . .

SHRI DIPEN GHOSH; That is also one of the ills of the society.

SHRI DINESH GOSWAMI: That is also one of the ills, yes. Various types of ills today are pervading the society, and when we deal with this situation we must make a distinction between the individual crimes where a man commits a murder for individuals gai$_n$ or individual pleasure, and the group crimes where a group commits a crime, may be because it believes in something or, may be, it wants to destroy something. Today there his been a general complaint throughout and it is my view that never before was the situation so bad and the air so steeped or filled with so much of violence since independence as it is today. There have been very serious allegations throughout. Violence is on the increase because the politicians are in league with criminals in many parts of the country. Serious allegations are made against members of legislatures, against persons in political life, maybe, from this party or from that party. In the past even when a single allegation was made against a single person in political life, very serious action was taken. For example, an allegation was made after all, crime thrives in an atmosphere where there k no rule of law—that Rs. 2 lakhs were being offered to buy an MLA. I do not know whether it is correct or not. In Pandit Nehru's time a Member had to leave 'nis membership; he was forced to resign; in fact, disciplinary action was taken. There was an allegation that thai Member took Rs. 20,000 from a business house to plead the case of that business house with Members of Parliament. ..

SHRI NIHAR RAN J AN I.ASKAR: How does it come in here?

SHRI DINESH GOSWAMI: It does, it does come in, Mr. Minister, when there is a feeling in this country that even those who are administering the country are corrupt, do you except the society to be pure? It does come because you have encouraged corruption throughout, and violence comes from corruption in life. There is corruption all through. And today the forces which are there to maintain law" and order feel demoralised. In matters of election it is not individual merit that counts. It is favouritism that counts Therefore, there is total demoralisation in the society. And the honourable Minister takes it very ligtly. Mr. Home Minister, if the situation had been so bright, do you realise the typ$_e$ of security that you have introduced in Parliament today?

SHRI NIHAR RANI AN LASKAR: It is because you have asked for it.

SHRI DINESH GOSWAMI: I have not? What for are you providing it? Because you feel that Members of Parliament and Ministers are not safe within the precincts of Parliament House. What does it indicate?

SHRI NIHAR RANIAN LASKAR: Members of Parliament have asked for it and that is why it is provided to them.

SHRI DINESH GOSWAMI; No. We have protested against that. If the Members of Parliament have asked for it, it is because the situation is such that in Delhi where the strictest security arrangements are made we ore not safe. And the Minister still says that there is no violence

and there is a marked improvement in the law and order situation.

Also I have noticed that the Government has not tried to make any change in the social structure, though times without number we have demanded that One reason, why violence is increasing is because violence is projected in the media in such a manner that whoever indulges in violence becomes a hero. Nothing has been done to correct this impression. A young boy[1] or girl who sees a film feels that there is nothing wrong in it.

Assam and Punjab have been mentioned and it appears that the Minister considers the situation there as a law and order problem. The hon. Minister Says there are stray incicidents of violence. What are these stray incidents? Seventeen people have died in a blast in the railway station. And there were five blasts. Yesterday for the first time a raid was sought to be attempted in Gauhati where one C.R.P. jawan was dead and nine others seriously injured. Do not take Punjab and Assam as law and order problems. Violence has grown becaus$_e$ today State violence has growfl throughout the country.

Take Assam for example. No youth in the rural areas sleeps at his home at night. He goes and sleeps in the fields because the Police come without any authority of law, takes him to custody and beats him up. The allegation is that para-military forces kill people brutally. Have you made any inquiry into this allegation? You seem to take some sort of pleasure in saying that the situation has improved. T can say very emphatically that if you feel that there i$_s$ improvement in the situation it is a lull before the storm and it is a peace of the grave. Unfortunately again instead of trying to locate the criminals and bringing them to book, the State has created an air of violence by killing innocent people in the name of encounters. Newspaper reports and periodicals have referred to it. I do not find any enquiry on the part of the Government being conducted. In any other democratic country which believes in the rule of law, even if there is one such allegation that the State authority has killed one individual, there would be an enquiry.

I ask the Home Minister. Have you made any socio-economic study of the present situation as to why violence has grown? Unless a socio-economic study is made of this problem, you cannot solve it. It appears from the statement that you want to compare saying that there were so many murders yesterday in Delhi, but today there are only so many. There are three types of statistics, lies, damn lies and statistics. One type of statistics throws light. The other is only a lamp post which is used by a drunken man to keep himself steady. The Government seem to use this type of statistics and not (he one which will throw light.

Will you look into all the questions asked o$_n$ this issue? Most of the questions on detrioration of law and order situation in Delhi have not come from the opposition, but from the ruling party members. Still you say that there is no deterioration. Whom are you trying to fool? Whom are you trying to fool. Mr. Minister'.' Tn Delhi every day we hear about bride burning. We bear *ofte$_B$ about all* sorts of crimes against women. And, in Delhi, Sir, whatever happens gets projected in the Press. But, whatever happens i$_n$ the rural areas, does not get projected in the Press. But the situation in the rural areas is much more difficult. Therefore, I would like to know from the honourable Minister whether, instead of taking a complacent attitude and trying to tackle the problem of Assam or Punjab as merely a law and. order problem, he will try to have really a political approach to these problems. *J* would also like to get tin assurance from him that at least he will not use State violence against innocent peopl$_c$ because where violence is used by the State, it leads to a chain reaction of violence. I would also lik$_e$ to know whether $_a$t any Point of time the Government had made any socio-economic study of the situation in this country to tackle this problem. T would also like to know—and this is a question which, has been repeatedly asked by different Members—whether the Government has given it$_s$ thought to the various important recommendations made from time to time on this and. *if* so, what Die attitude of the Government *i to these

[Shri Dinesh Goswami]

important recommendations to make improvements in the police forces. Thank you, Sir.

SHRI MADAN BHATlA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the honourable Minister of State for Home Affairs to the last paragraph of the statement. It says:

> ."The maintenance of law and order though primarily is the responsibility of thg State Governments, the Central Government also gives utmost priority to this subject."

Then, Sir, the fifth line reads like this:

> "The assistance of Central police forces is also made available to them as and when asked for."

1 would respectfully submit that this particular statement is constitutionally not wholly correct and accurate. I would like to draw the attention of the honourable Minister to article 355 of the Constitution. It says:

> "It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance, etc.. etc."

So far as article 355 of the Constitu tion is concerned, it not only does provide that there has to be a request for an application from the State Govern ment for providing assistance to deal with internal disturbance, but it also says that it is the duty of the Central authority to take all possible steps to deal with domes tic political or communal violence. And, Sir, I feel—and this has been said by many honourable Members—that the crimes in the country have to be divided into three categories: One., political and communal violence; second, economic offences: and the third, ordinary crimes against persons and property. So far as the first category of crimes is concerned, it is not the primary responsibility of the State Government alone, but it is equally the primary Constitutional duty of the Central authority also to deal with them.

Sir, this particular article has remained dormant during the 'Mt 35 years because of some executive or administrative convention that the State Government should ask for aid and the Central Government would provide that aid. But I would like t0 draw the attention of the honourable: Minister to the corresponding provision in the Constitution of the United States which has been interpreted by the U.S. Supreme Court It is section (4) of article 4 of the U.S. Constitution and it says:

> "The United States shall guarantee to every State in this Union a republican form of Government and shall protect each of them against invasion.

And, Sir. tlie next sentence reads like this:

> "... .and oa application by the Legislature of Executive when the Legislature cannot be convened, against domestic violance."

So far as the American Constitution is concerned, it has specifically provided that there has to be a request from the State authority to deal with domestic violence. But when this article came up for inter pretation by ike United States Supreme Court, this restriction placed upon the federal authority was nullified. This is known as Deb's case. The United States Supreme Court held that domestic violen ce may affect execution of powers entrusted to the United States by the Constitution, and in such a situation the United States has the power and the duty to use the entire strength of the nation to enforce in any part of the land full and free exercise of all national powers and the security of 'all rights entrusted by the Constitution. So I respectfully submit that 1 would like to make a suggestion to the hon. Minis ter of State in this regard that so far es organised political and communal violence is concerned it is time the Government of India to consider the possibility, and in fact, the necessity of establishing a machinery

which *wilt* automatically swing into action I lo deal with communal or political violence wherever and whenever it takes place, and it does not have to wait for an application or request from the State executive authority.

So far as economic offences are concerned 1 would again like to draw the attention of the hon. Minister to article 323B because in the last few years this country has been witnessing a horrible spurt in the commission of economic offences. Article 323B says:

"(1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect to all or any of the matters specified in clause (2) with respect to which such legislature has power to make laws.

(2) The matters, referred to in clause <1) are the following, namely:—

(a) levy, assessment, collection and enforcement of any tax:

(b) foreign exchange, import ant! export across customs frontiers;

(c) industrial and labour disputes;

(e) ceiling on urban property:

(g) prod action, procurement, supply and distribution of foodstuffs (including edible oil-seeds and oils) and such other goods as the President may, by public notification, declare to be essential goods for the purpose of this article and control of prices of such goods:

(h) offences against laws widi respect to any of the matters specified in sub-clauses (a)' to (g) and fest in respect of any of those matters:

(i) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (h).'[1]

I will respectfully submit it is high time that the Government of India now should consider the establishment of tribunals under article 323B for speedy trial of economic offences, because this article further gives the power to the appropriate legislature to provide for the procedure including provisions as to limitation and rules of evidence to be followed by the State tribunals. In these tribunals, by law, the Legislature can provide for speedy trial by a_n appropriate procedure and can provide for law providing for the rules of evidence which would be less than in the ordinary course. And I respectfully submit —and this is my strong plea *to* the Government of India through the hon. Minister— that time has come when this particular constitutional provision should be invoked by Parliament relating to the Centra! laws for the establishment of the tribunals for the speedy trial Of the economic offences and deterrent punishment to the offenders.

So far as the ordinary crimes are concerned, I respectfully submit that in view of the shortage of time, it is not my intention to go into the various social and economic causes which have led to the spurt in these ordinary crimes. But there are legal factors to which I would like to draw the attention of the hon. Home Minister which may be dealt with suitably by suitable amendments to the various laws. The first and the foremost thing is the liberal and almost reckless grant of bail! by the courts to various accused. If l remember correctly, a report has beer submitted—it was so reported in the newspapers—by the Lt. Governor of Delhi tc the Home Ministry in which he has advocated a necessary action in this regard ant has brought to the notice of the Govern mem the manner i_n which bails are being granted by the courts. Hon. Minister car correct me if I am wrong. The offender who are granted bails come out of Jut/ and commit still more serious and heinon crimes. A law has been laid down by fhi Supreme Court that bail is a rule and th refusal to grant bail would be an excep tion, I respectifully submit that it is higl

[Shri Madan Bhatia]

time in the context of the prevailing Indian conditions that this law laid down by the Supreme Court should be reversed by suitable amendments in the Code of Criminal Procedure.

The second thing is long and protracted trials. This is a problem which is confronting us every day in the courts and it is too well known to the Government of India for me to stress it more. Suitable steps should be taken in this regard.

The third thing is the laxity in the grant of punishments. This is something which has been agitating me very much. We have amended the Indian Penal Code to make death sentence an exception and the Indian Penal Code says that the grant of death sentence will be an exception and not a rule. I respectfully submit that in this country human life has become so cheap that at the drop of an eyelid, a person takes out a gun or a dagger and kills an innocent citizen. It is time that law is reversed. The law should be such that the death sentence in this country should be made a rule and not an exception. An exception should be provided in cases in which death sentence is not to be given.

The fourth thing is—and this I would like to say with considerable trepidation —that the highest judcial institutions in the country, it appears, are showing more concern for the rights of criminal on the basis of imagined constitutional rights of the criminals and less concern for the safety and security of the society. It is time that self-restraint ought to be exercised by the highest courts and judicial institutions in the country.

Lastly. I would like to make this submission for kind consideration of the hon. Home Minister. It is not possible to check crimes unless we breed respect -for law. We cannot breed respect for law unless we instil in all potential offenders fear of the law and the fear of law can come only if the potential offender knows ,hat there will be prompt apprehension, ithat there would be a speedy trial and that there would be deterrent punishment. Will the hon. Minister consider these points?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALT): Now the reply by the hon. Minister.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAK: Sir, at the outset I would like to say that it is quite natural that most of the hon. Members who have spoken here have shown their concern about the incidents which are happening unfortunately in some parts of our country, and in the process they have mentioned particularly Assam, Punjab and also, of course Delhi Sir, the Government is not only concerned about what is happening in all these places but we are also determined to curb the activities of these extremist elements who have taken the law into their own hands and creating chaos in the society and killing innocent people here and there and for what purposes we do not know. Sir, of course, I will come to Assam first. I think, Mr. Goswami also has raised about it. What we have said here is that we have now identified those extremist groups who are working in Assam. Initially, there was an agitation in the name of foreigners. And we have tried our best to talk to them and come to some sort of settlement. But, unfortunately, because of their obstinacy, it was not possible to come to an agreement and we always said that this sort of agitation always goes beyond the control of the people who start it and it goes into the hands of anti-social and extremist elements. Exactly that is happening in Assam and also in Punjab. Now, as you see, after the establishment of the present Government in Assam, life is gradually coming to normal. People arc now moving freely throughout the State. I think, my friend from Assam also cannot deny this fact, and everything is becoming normal. But there are some groups of extremists people.

SHRI AHT KUMAR SHARMA: May I jtist seek a clarification, Sir?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, I am not yielding...,

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: He | say* that the State is normal...

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Let me first say what I dant to say. Sir, what I was telling is that a group of few extremists arc now trying to come together in the North-Eastern areas and are trying this sort of sabotage here and there. The latest incidents which Mr. Ooswami has mentioned is also a fact, and because of our intensification of our Intelligence and other things, we have identified the activities of these extremists and we are trying to capture them. As a result of this, the incident of last night has taken place. I can tell you how the normalcy is coming to Assam. I will give you certain facts so that on the basis of that, one can realise this.

Sir, the law and order situation has improved a lot since the establishment of the present Government in Assam. I can give you some figures of the period between March, 1983 and October, 1983, I am giving the figures of Assam. In March 19S3, the number of cases of murder was 183; arson cases were 2,115; cases of bomb explosions were 64; number of cases • of recovery of explosives, arms and ammunition was 59; number of deaths in police firing was 17. In April, 1983. cases of murder were 121; arson cases were 2.919 bomb explosions were 43; cases of recovery of explosives, arnv- and ammunition were 48; and the -i--ths in police firing were 12. Now coming to the month of May. 1983, the cases of murder were 31; arson cases were 18; bomb explosion cases were 10; cases of recovery of explosives, arms and ammunition were 21; death in police firing was nil. In June, 1983, the cases of murder were 11; arson cases were 26; bomb explosion cases were 12, cases of recovery of explosives, arms and ammunition were 43; death in police firing was nil. Similarly, in July, 1983, there were 11 Cases of murder, 4 cases of arson, 6 cases of bomb explosion, 29 cases of recovery of explosives, etc. and death in police firing was nil. That means, no police firing was resorted to. In the month of August, 1983, the cases of murder were only 2, arson cases were 4, cases of bomb explosion were 10, cases of recovery of explosive-',, etc. were 6, and again death in the police tiring was nil.

In the month of September there were ten cases of murder, one case of arson, ten bomb explosions and twelve eases of recovery of explosives, arms and ammunitions and no case of death in police firing. The latest figures that I have with me relate to the month of October. There were seven murders, two cases of arson, two cases of bomb explosion and twelve cases of recovery of explosives, arms and ammunition and no case of death in police firing. So, Sir, this is the trend. . .

SHRI SANKAR PRASAD MTTRA (West Bengal): There are some reports that some terrorist have voluntarily surrendered arms. Have yon got any facts or figures about that?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): इनके पास बालयंटरी मर्डर्स की फिगर्स हैं ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, this is the report. We havo all the information with us but I am not just now giving you the details. A number or arms and ammunitions have been captured by our forces. This is the position when Assam is fast returning to nomal-cy, the extremist groups are trying to create this situation here and there. But I can assure the hon. House and the hon. Members present here fhat the Government will do its best to bring normalcy as fast as possible and curb the activities of the extremists as far as possible. So far as the position of Punjab is concerned

«ft 3PT5«ft JKTT3 *m*r: %TT %

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, I would, like to say that a lot has been said about Punjab in the last two days during the question answer sessions ;ind in debate form also. But even then the hon. Members have again raised the question of Punjab. Sir, this has been discussed in great detail in this House, as I have already said. I would like to remind the hon. Members that after the promulgation of the President's rule and *e promulgation of the Punjab Disturbed

[Shri Nihar Ranjan Laskar]

Areas Ordinance, 1983, and the Chandigarh Disturbed Areas Ordinance, 1983, and the Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special Powers Ordinance, 1983, as a result of special operations from the middle of October, 4470 undesirable persons have been 'arrested till the 10th November and 282 weapons with a large quantity of ammunitions have also been recovered up till now in Punjab. Special efforts against extremists have also been started, showing some ʳes» *s Tn some cases the extremists have either died in encounters or tnjy have Deen arrested in quick police action.

Sir, the hon. Members have again referred to the situation in the State in terms of finding a solution and have said that we have no political will and all that These things have been repeatedly stated. But the Government has made all efforts to find a solution, talks have been held »t various levels and at many times but they have remained inconclusive.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : असम से पंजाब चले आए सारे एक्स्ट्रीमिस्ट ।

SHRl NIHAR RANJAN LASKAR: The Akali leaders were invited by the Home Minister to resume discussions. Trie Home Minister also made some appeals through thc press statements and on the floor of both the House of Parliament. Recently, the Prime Minister herself has reaffirmed that a settlement to the issue of Chandigarh and all the other demands could be had through discussion. It is not for any lack of effort on the part of the Government that the matter i_s still hanging fire. We are making every effort and we are keeping our doors open for discussions. But, somehow they are not co-opera tins. This is the position today. We have given a direction to the State Government to see that the actvities of the extremist groups are curbed which are creating havoc there. We have asked them to curb these activities as early as possible and that drastic) measures should b_e taken against them.

Now. Sir, with regard to Delhi I would like to say something. Sir, Delhi is a growing city and the requirements of eff-ectively policing this city are also constantly growing. It was only after taking this thing into consideration that on the resumption of the Government in 1980 a number of steps were taken by the Gove

rnment to improve the efficiency of Delhi Police. I would like to say what we have done in regard t_0 the strengthening of the Delhi Police. Five more battallions for the Delhi Armed Police were sanctioned Then, a number of vehicles have been added to the feet of the Delhi Police. A number of gadgets huve been purchased for use by the Delhi Police during the Asian Games and the Non-Aligned meet These gadgets have lesulted in the better performance of the Delhi Police. Thr-t are with the Delhi Police now.

In regard to the iotiviiies of the extre mists in Delhi, $ther_e$ are two aspects in this which I would Ike to point out to-the House and which should be borne in mind. One is the incident of bomb ex plosions in th_c capital making use of ex plosives similar to those used •:•. Chandi-grah, in Punjab. The other is the move ment of extremists into Delhi from out side. Since 1981, there have been 17 ex plosions in Delhi. Out of this, there is definite evidence to indicate the involve ment of extremists in ten such cases. We $Viav_e$ definite evidence with us. Three of these ten cases have been fil ed as untraced ;md th_e remain ing seven cases are under in vestigation now. Out of this, it has been possible for the Delhi Police to work out three cases with the arrest of three per-^jns, one of whom had been apprehended recently by the Punjab Police. Non-bail able warrants in respect of some other otermists suspected to be involved in these cases have been issued. While in the remaining cases, crude country-made bombs were found to have been used, in respect of the recent explosions at the two cinema houses and at the New Delhi. railway station, there is evidence of hand grenades with Indian markings having been used. Tn order to deal with move ment of extremsts in Delhi, police presence in Delhi has been intensified. ft was only

ihiough the efforts of one of the police pickets Put up for this purpose that a suspected extremist was apprehended by the Delhi Police on the 24th October 1983 during the Nirankari Samagam. Not only that. The police have also recovered a 1.3 mm. gun, a country-made pistol and cartridges.

Then, there is another point which I should like to mention here. Mr. Yadav is not here. Mr. Satya Pal Malik was also mentioning about this. They have made reference to the pay scales of the Delhi, Police. This has also been referred to by some friends here. The pay scales of the Delhi Police are definitely lower than those of Haryana, where the pay scales have been revised recently. But there is not much difference in the total emoluments including allowances. This is the position. Revision of the pay scales of the Delhi Police will be one of the items of work ot the Pay Commission which has been set up recently. We are looking into this problem.

Then, certain things have been said here. It is not correct to say that the Delhi Police have not been apprehending the criminal gangs. Somebody said that the Delhi Police is not very active. This i; not a fact. The Delhi Police have been able to work out some important cases, which occurred during the year. Three persons responsible for sensational cases of robbjry in South Delhi, at Hem Kunt, Gulmoh-ur Park and Defence Colony on 13114.6.83, 7)8.6.83 and 7.8.83 respectively have been arrested. The remaining suspects, along with some of fhe stolen property, are likely to be arrested in due course. Eight members of an interstate gang of criminals headed by Sunil. Tyagi, who was wanted in at least 35 cases of robbery, murder, dacoity and attempt to murder in Delhi and U.P. were arrested on the night of 17J18-9-83. Of this, eight cases, all heinous offences, are of Delhi and include an armed robbery, involving Rs. 3.5 lakhs, from the DDA office in the Shakarpur area. On 1st November, 1983. three members of a gang, involved in at least twenty cases in Delhi and U.P. were arrested. This is the position. Because of the stregthening of the Delhi Police and also because of the recent instructions which have been issued, the Delhi Police have been able to work out some cases alleged and many culprits have been arrested .

With reference to the various categories of crimes, the number of cases in 1983 have been...

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन्, मैं एक जानकारी मंत्री महोदय से चाहता हूं । श्रीमन्, यह जो सुनील गैंग का जिक्र मंत्री महोदय ने किया, इस गैंग का पकड़ा जाना बहुत मुश्किल था । यह बहुत खतरनाक गैंग है । उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स का इतना सोफिस्टिकेटेड गैंग नहीं है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बेसिकली वे लोग मेरठ के रहने वाले हैं । इनको मेरठ, मुजफ्फर-नगर, गाजियाबाद, हापुड़ में अड्डे हैं और वहां इनके कान्टेक्ट्स हैं । वहां उनके लोग हैं जो उनका मुकदमा लड़ते हैं, उनको हथियार देते हैं । उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों की पुलिस से संपर्क स्थापित किया और वहां पर जो इनकी लाइफ लाइन है, उसको काटने की कोशिश की ?

SHRI NIHAR. RANJAN LASKAR: Sir, I think I have already stated about the Tyagi gang of dacoits We have already contained them and we are after them.

Here with reference to the various categories of crimes which have been worked out by Delhi Police. . .

श्री सत्यपाल मलिक : आप मेरी बात समझे नहीं । दिल्ली पुलिस ने वहां से जहां से आरजीनेट करते हैं ... **(व्यवधान)** ... मेरठ, गाजियाबाद बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर ...

SHRI N1HAR RANJAN LASKAR: At the moment I am talking of Delhi. 1 will give you the number of cases that have been worked out in various cate gories.

In 1983 the reported number of dacot-ti$» in Delhi is 13 and out of these 13 cases the Delhi police have worked out 10 cases, the number of persons arrested *it* 43.

Murder cases in Delhi in 1983, reported 210, police worked out 130 cases and the number of persons arrested is 179.

Attempt to murder cases reported 184, worked out by police 156 and the number of persons arrested 287.

Robbery cases reported 183, worked ont by police 85 and the number of persons arrested is 178.

Snatching cases reported 108, worked out 45 and the number of persons arrested is 67.

So, Sir, I am just giving all these figures to snow that the Delhi Police has geared up and a lot of cases have been worked out and a number of culprits have been arrested.

Then, in the course of the debate many Members have metitioned about the bank security force. Of course, this proposal for creating a bank security force is under consideration of the Ministry of Finance. We have referred to them this matter. Whatever other suggestions have come up during today's debate will also be referred to them for coming to a conclusion.

Another point that has been raised by many Member is about separation of in-vestigation and law and order in the police. We are already considering this proposal and it is under consideration.

Now I would like to deal with certain points raised by the individual Members. *Mr.* Kalraj Mishra—he is not there-made a reference to some important incidents in some parts of Eastern U.P.. 1 think. Central Government was in touch with the State Government in this sort, of incident and We rfaall convey the feelings expressed by the hon. Members her$_e$ to th$_e$ Government of Uttar Pradesh and I am sure the State Government will give due consideration to the views expressed by my friends here.

Then, he has also mentioned about the Sultanpuri incident.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, कलराज मिश्र यहां पर नहीं हैं। एक मिनट का समय चाहता हूं ... **(व्यवधान)** ... एक सेकेंड । इसमें आपका भला होगा ।

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भावनाओं को वह लिख देंगे और केन्द्रीय सरकार उनसे संपर्क बनाये हुए है, जहां तक मैं समझता हूं, मंत्री महोदय ने यही कहा है । लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री क्रिमिनलों के साथ रहता हो, उनके साथ बैठता हो, क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करता हो, तो उस हालत में आप क्या करेंगे ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I cannot follow this argument.

श्री रामेश्वर सिंह : गोरखपुर में तिवारी और साही को मुख्य मंत्री अपने घर बुला कर बैठाते हैं **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): रामेश्वर सिंह जी, आप बैठिए ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: On the one hand they say that the Centre is very strong and we are interfering in States' activities, and on the other they want us to call upon the State Governments to do certain things. We are keeping a balance. About the Sultanpuri incident...

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा कहना यह है कि ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत अली): मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : आप किस के पास जाएंगे (व्यवधान) जब तक मुख्य मंत्री खुद (व्यवधान) उस हालत में आप क्या करेंगे ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: This sort of allegation does not help the situation. If you have anything positive, you must tell me. It is no use saying somebody is involved. Why should he be involved in such activities?

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीपति मिश्रा खुद इनवाल्व हैं क्रिमिनल्ज को बढ़ावा देने में।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: This is entirely wrong thing to say in this House.

Again he was referring to Sultanpuri incident and he was asking for some sort of an enquiry. I would like to inform the hon. Members that the Lt. Governor of Delhi ordered an enquiry into the incident of firing in Sultanpuri in which four persons lost their lives. The enquiry was conducted by the Additional District Magistrate and a report has been submitted to the administration just a few days back. The report is being examined by the Delhi Administration and after this, action will be taken.

Mr. Jha made one point which 1 remember last time also he made—about the peace force at t'ne village level. The position is like this. He has suggested that Peace Committees may be favoured at block level to ease communal situation in these areas, or something like that. I would like to inform him that in the guideline issued by the Central Government, to the State Government, it has been suggested that Peace Committees should be formed in districts and localities. We have not said at block level but we have said at districts and localities, t only hope that the State Governments would do the needful. We are also getting reports from some of the State Governments.

Then some hon. Members have also suggested that the police force should be modernised. The Central Government agrees with this view and we have also taken certain steps in this regard. We have already made a special provision of Rs. 100 crores for the upliftment and betterment of the police force or modernisation of the police force. Funds are being released to the State Governments for purchase of vehioles, wireless equipment, computers scientific aids for investigations, training equipment etc. etc. We hope, with the implementation of this scheme, the State police forces will be better equipped for discharging their res-ponsiblities properly..

Then some hon. Members also raised the point about tackling the dacoity problem. The Central Government has impressed upon the State Governments from time to time the need to take coordinated action to tackle this problem on a continuous basis and to ensure coordination among the Governments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where this problem is a little serious, and to deal with inter-State dacoity menace, a joint Coordination Committee comprising officials of the three States has been constituted. I think after the formation of this Coordination Committee, some results have come.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: What about the Bank Security Force?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: 1 have already said that we have referred it to the Finance Ministry. They are considering this thing. And whatever you have said today, that also I will send to them.

Then a mention has been made about incidents on the railways. Following measures have been taken to prevent incidents of crimes, including robberies, and dacoities on the railways. The, drivers of the trains have been directed to sound the

[Shri Nihar Ranjan Laskar]

distress whistle if the train is brought to a sudden unscheduled halt so that the escort party could be put on the alert. There are escort parties already provided in most of the trains. So, this, is 4.P.M. one. Then, Coach Attendants have been instructed to remain vigilant and prevent entry of unauthorised passengers into reserved compartments. The Research, Design and Standards Organisation of the railways has been advised to suggest improvement in the locking arrangements of sliding doors of compartments, improvement in the vestibules to prevent unauthorised entry and provision of better lighting facilities in and outside the compartments. Government Railway Police, who are responsible for safety and security of passengers travelling in trains and their belongings, are making all efforts to control crime on the railways by providing escorts on trains, surveillance over criminals arresting and prosecuting them in specific cases. Railway Protection Force is assisting the Government Railway Police in this regard. Not only that. Recently the Central Government has written to the different Chief Ministers to help us in this regard.

One or two hon. Members raised the question of illicit arms and pilferage of military arms from depots, etc.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप बिहार की ला एंड आर्डर के बारे में बता दीजिए, तो अच्छा रहेगा ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: We have already issued instructions to the State Governments to unearth illicit arms. The State Governments have also intimated action they have taken so far in this regard. We are getting regular information about this. The problem of checking pilferage of military arms and ammunition has also been examined in depth and detailed instructions have also been issued to the respective authorities in this regard.

Now, there is one more thing—ihe last point. Many hon. Members have asked about the Police Commission's report. We have already accepted a number of recommendations. I think Mr. Jha also referred to the Police Commission. The NPC submitted eight reports to the Government. The first report Was discussed at a conference of Chief Ministers in June 1979. This report largely dealt with welfare measures for policemen. Recommendations of the first report have been implemented by all the State Governments and Union territories. This is the position of the recommendations. All the Chief Ministers accepted them and they implemented them. The remaining seven reports were released in March 1983. All the State Governments and Union territories were requested to take appropriate action on those recommendations. As you know; Sir, police being ;i State subject, it would largely be the State Governments who would be concerned with implementation of the recommendations. However, most of the State Governments have informed that they are actively considering the recommendations. Recently they have also been reminded by our Home Secretary to expedite implementation of these recommendations.

There is just one more point, about the overall situation. I think it was Mr. Jha who said that year by year the instances are increasing. I wjll show some figures which would prove that it is not a fact. I would start not from 1980 but from 1978. The crime figure in 1978, putting together everything—murder, robbery, etc. —all over India was 43,407. In 1979 it was 44,086: in 1980 it was 37,586; in 1981 it was 30,646. So. what he has said does not tally with the figure.

SHRI DIPEN GHOSH: What aboui the 1978 figure.

SHRI NIHAR RAN J AN LASKAR: Very large number. I do not want to go into all the figures and bother the House. . . *(Interruptions)* . . .Which one do you want?

श्री शिव चन्द्र झा : श्राप 1 ग्रोर 1982 के भी फिगर्ज बता दीजिए ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: In 1981 it was 26,846. In 1982 it was 27,162.

SHRI DIPEN GHOSH: All over India?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I am giving the Delhi figure. In 1983, up to 31-10-1983 it was 23,067. So, Sir, these are some facts.

Then about the situation in the northeastern States, not only in Assam, because the problem is that of the northeastern region as such. In Manipur and Mizoram, the number of cases of crime has come down and the situation is becoming normal. In Mizoram, since January 1982, 301 persons have been arrested and about 489 MNF personnel—you know that group—have surrendered. About 270' weapons have been captured. There is a sense ot confidence now prevailing among the civilians. I have myself seen in Aizawl that people move about freely. In Manipur, since September 1980, when counter-insurgency operations were stepped up, 591 extremists have been arrested, and 247 surrendered. The situation is under full control now in Manipur. In Tripura, you know better, Mr. Ghosh, that the extremist leader Jamatia surrendered to the Government with 200 of his supporters. In April 1983, Chuni Koloi, another extremist leader, was arrested. The situation is, more or less, under control. If only some of the Members had also cooperated, things would have come to normalcy, very soon.

In the end, I would say that I am grateful to all the hon. Member for the points they have raised during the course of the discussion....

SHRI DIPEN GHOSH: You have not covered Bihar.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: . . .because it has provided us with the thinking of the House regarding many aspects of the law and order situation. We have been benefited by this. While I have attempted to answer some of the major points raised by the hon. Members, I should reiterate that the Government is not complacent at all—some of them tried to impute motives; but we are not at all complacent—and is always alive to the overall situation and will continue to do its best to see that the law and order situation is fully brought under control.

As I have already stated the law and order matters are mainly the responsibility of the State Governments. Whatever suggestions have been made are matters for consideration. Your suggestions I h'ave noted, but basically and mainly, the law and order matters are the responsibility of the State Governments. We are aware of the overall situation and (the need to take prompt action at all times. The vigil maintained by the Government is constant, and all efforts are being made to ensure a climate of peace in the country.

REFERENCE TO THE REPORTED RECENT BREAK-DOWN OF MEDICAL SERVICES IN CALCUTTA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED REHMAT ALI); Now Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI) in the chair.

SHRIMATI MONIKA DAS (Karna-taka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of this august House to an unhealthy conflict in West Bengal, in the Health Department. Mr. Vice-Chairman, Sir, last fortnight six children died due to non-availability of drugs and Oxygen 'in hospitals. Fifty thousand out-patients were being turned away every day from the free Government hospitals, not one or two. *(Interruptions)* Thousands of indoor patients were sent back home, patients suffering from various diseases, due to non-availability of medicines and other things. *(Interruptions)* Due to non-availability of medicines and other things, doctors were very much unhappy because it is the duty of a doctor to cure patients. They did not get sufficient medicines and they did not even get some respect from this Department, the Health Department. Then